राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 09 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-218 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

पीएम मोदी के वडोदरा कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह,एक घंटे में फुल हुईं सभी सीटें

42 हजार से ज्यादा लोग प्रतीक्षा सूची में, पहली बार बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में निजी डिजिटल मंच से पंजीयन और प्रवेश की व्यवस्था

वडोदरा ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में होने वाले कार्यक्रम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कार्यक्रम के लिए निजी डिजिटल मंच के माध्यम से पंजीयन शुरू होने के महज एक घंटे के भीतर सभी उपलब्ध सीटें भर गईं। इसके बाद 42 हजार से अधिक लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने सामाजिक माध्यम के जरिए इसकी जानकारी दी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए पहली बार निजी डिजिटल मंच के माध्यम से पंजीयन और प्रवेश व्यवस्था का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। वडोदरा नगर निगम ने कार्यक्रम में आम लोगों के लिए निःशुल्क पंजीयन की सुविधा शुरू की थी। पंजीयन खुलते ही बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया और करीब एक घंटे में सभी उपलब्ध सीटें भर गईं। क्षमता पूरी होने के बाद पंजीयन बंद कर दिए गए और अतिरिक्त आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया। क्यूआर कोड से होगा प्रवेश सफल पंजीयन कराने वाले लोगों को उनके खाते के माध्यम से डिजिटल टिकट मिलेगा। टिकट में सुरक्षित और सक्रिय क्यूआर कोड होगा, जिसे कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के दौरान जांचा जाएगा। इस व्यवस्था के जरिए पंजीयन, पहचान सत्यापन, प्रवेश और सीट प्रबंधन को एक ही डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है। इससे कार्यक्रम में भीड़ को व्यवस्थित करने में प्रशासन को मदद मिलने की उम्मीद है। 326 किलोमीटर लंबे माल गलियारे का उद्घाटन प्रधानमंत्री वडोदरा दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के तीन खंड प्रमुख हैं। इनकी कुल लंबाई 326 मार्ग किलोमीटर है और निर्माण पर 20,700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री चार स्थानों से मालगाड़ी सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वडोदरा और टांडा रोड के बीच नई यात्री रेल सेवा की शुरुआत भी करेंगे। तीन रेल परियोजनाओं की आधारशिला कार्यक्रम में

प्रधानमंत्री तीन बड़ी रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।

झारखंड हाई कोर्ट- महिला के कपड़े उठाना हर स्थिति में रेप का प्रयास नहीं

26 साल पुराने मामले में अदालत ने निचली अदालत का कहा- महिला की गरिमा भंग करने और आपराधिक बल के इस्तेमाल का मामला

रांची ।

झारखंड हाई कोर्ट ने बलात्कार के प्रयास से जुड़े 26 साल पुराने एक मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि रात में किसी महिला के घर में घुसकर उसके कपड़े उठाने की कोशिश को हर स्थिति में भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। अदालत के अनुसार, ऐसी परिस्थिति में यह महिला की गरिमा भंग करने और आपराधिक बल के इस्तेमाल का अपराध हो सकता है। यह फैसला न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया। फैसला 31 अगस्त को सुनाया गया था, जबकि इसे सोमवार, 7 सितंबर को सार्वजनिक किया गया। मामला करीब 26 साल पुराना है। घाटशिला सत्र अदालत ने 25 जुलाई 2006 को आरोपी को बलात्कार के प्रयास का दोषी ठहराते हुए चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले में बदलाव किया और बलात्कार के प्रयास के आरोप को अलग करते हुए मामले को महिला की गरिमा भंग करने तथा आपराधिक बल के इस्तेमाल के अपराध के रूप में देखा। अदालत ने 'प्रत्यक्ष कृत्य' को लेकर क्या कहा? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की योजना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया हर कदम अपने आप में बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं बन जाता। अदालत के अनुसार, बलात्कार किए जाने के पर्याप्त रूप से निकट कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य होना जरूरी है। पीड़िता ने क्या आरोप लगाए थे? मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी रात में उसके घर में घुसा और बलात्कार के इरादे से उसके कपड़े उठाने की कोशिश की। इसी आधार पर निचली अदालत ने उसे बलात्कार के प्रयास का दोषी माना था। हाई कोर्ट ने आरोपी के पहले ही करीब आठ महीने हिरासत में रहने को पर्याप्त मानते हुए उसकी सजा में भी बदलाव किया। फैसले के बाद यह मामला कानूनी व्याख्या और बलात्कार के प्रयास के लिए जरूरी तत्वों को लेकर चर्चा में है।

सवाल पूछने पर दिमागी नक्सल और नाराज़ फूफा जैसे अपमानजनक लेबल लगते हैं

पीएम मोदी की दिमागी नक्सलियों वाले भाषण पर राहुल गांधी ने बोला तीखा हमला

नई दिल्ली।

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए दिमागी नक्सलियों वाले भाषण के कीरब तीन हफ्ते बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को उन पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं और जवाबदेही से बचने के लिए ऐसे विवादास्पद शब्दों का सहारा लेती है। उन्होंने विशेष रूप से दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे का हवाला दिया, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की जान चली गई। राहुल गांधी ने एक्स पर ये बातें कहीं। उन्होंने टिना हैशटैग का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है उन्होंने कोई जवाबदेही नहीं बताया। गौरतलब है कि पीएम मोदी के समर्थक टिना फ़ैक्टर का ज़िक्र करते हैं, जिसका मतलब वे कोई विकल्प नहीं बताते हैं। यह पहली बार है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले तंज का जवाब दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार से सवाल पूछने वाले किसी भी व्यक्ति को दिमागी नक्सल कह देती है। सोमवार को हिंदी में किए गए अपने एक्स पोस्ट में राहुल ने कहा कि बीजेपी हमेशा निचले स्तर के अधिकारियों को दोषी ठहराती है और असली दोषियों को बच निकलने देती है, साथ ही, वह त्रासदी को रोकने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाती। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की सत्य निकेतन त्रासदी कोई अकेली घटना नहीं है और पिछले चार महीनों में राजधानी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं।

दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

रायबरेली ।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे के लिए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। वह अपने दौरे में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक भाग लेकर जिले के विकास की नब्ज टटोलेंगे तो पार्टी पदाधिकारियों से मिलकर संगठन के कामकाज का सच जानेंगे। वहीं, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राहुल का रायबरेली का यह दौरा अहम माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार शाम को रायबरेली पहुंचे। रास्ते में महाराजगंज में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हलोर व महाराजगंज में वह सभा करेंगे। इसके बाद शहर के प्रभुटाउन पहुंचेंगे। रात में भुएमऊ गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।

टास्मैक घोटाले और करूर गैंग का मुद्दे पर सीएम विजय ने विपक्ष को घेरा

चैन्नई।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में राज्य की सरकारी शराब कंपनी टास्मैक में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकार पर जोरदार हमला बोला।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए कि 2021 से 2025 के दौरान राज्य में एक संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसे करूर गैंग के नाम से जाना जाता था। यह हमला राज्य के राजनीतिक गलियारों में गरमाहट पैदा कर गया है, खासकर तब जब सत्ताधारी दल नई-नई सत्ता में आया है।

मुख्यमंत्री विजय ने आरोप लगाया कि इस गिरोह ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर अवैध वसूली, टेंडरों में हेराफेरी और पैसों का अवैध लेनदेन किया।

उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उस समय यह विभाग पिछली सरकार के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के पास था, जिससे सीधे तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। विजय ने आरोप लगाया कि सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर निजी लोगों और राजनीतिक बिचौलियों को अनुचित रूप से ताकत दी गई थी, जिससे एक समानांतर व्यवस्था का निर्माण हुआ जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी।

उन्होंने सदन को बताया कि करूर और कोयंबटूर जैसे इलाकों में शराब खरीदने वालों से तय कीमत से अधिक पैसे वसूले जाते थे और स्थानीय बार मालिकों से जबरन उगाही की जाती थी, जिससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हुआ और जनता का शोषण हुआ।

मुख्यमंत्री ने सेंथिल बालाजी के भाई वी. अशोक कुमार का नाम लेते हुए उन पर फर्जीवाड़े, टेंडर में गड़बड़ी और ट्रांसपोर्ट व खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट से अवैध

पैसे ट्रांसफर करने का सीधा आरोप लगाया, जिससे घोटाले की जड़ें और गहरी होती दिख रही हैं। अपने भाषण में, विजय ने 1967 में सी.एन. अन्नादुरई, 1977 में एम.जी. रामचंद्रन और 1983 में एन.टी. रामा राव (आंध्र प्रदेश) की ऐतिहासिक राजनीतिक जीतों का जिक्र किया।

पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल से नकली पीएमओ अधिकारी गिरफ्तार बंदूक भी बरामद

मुंबई ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई में होने वाले कार्यक्रम स्थल, नीता अंबानी कल्चरल सेंटर, से पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है।

इसमें से एक व्यक्ति के पास से एक लोडेड बंदूक बरामद हुई है। गिरफ्तार मुख्य संदिग्ध खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का अधिकारी बता रहा था।मुंबई पुलिस ने 24 वर्षीय रोहन पारेख नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पीएमओ का एक नकली पहचान पत्र मिला। सुरक्षा अधिकारियों को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ, जिसके बाद जांच करने पर पहचान पत्र फर्जी निकला। रोहन एक निजी बॉडीगार्ड के साथ घूम रहा था, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से भरी हुई पिस्तौल बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।

पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर इलाके में पहले से ही विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) और मुंबई पुलिस की कड़ी तैनाती थी।

इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, फर्जी पहचान पत्र के साथ संदिग्ध का कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक का सवाल खड़ा करता है। मुंबई क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच कर रही है। एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि पारेख ने इस फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल और कहां-कहां किया था, रोहन को यह कार्ड किसने उपलब्ध कराया था।

हल्द्वानी मैदान के 'शुद्धिकरण' मामले में हाई कोर्ट सख्त, बोला- पुलिस को जांच करने दें

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने निष्पक्ष जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने का दिया भरोसा

नैनीताल ।

उत्तराखंड हाई कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में हुई जनसभा के बाद रामलीला मैदान के कथित 'शुद्धिकरण' से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दर्ज प्राथमिकी और जारी जांच के बीच तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत पर सवाल उठाया। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और जांच से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएगा। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि जब प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच कर रही है तो उसे अपनी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ÷एफआईआर दर्ज होने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए।÷ स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दायर हुई याचिका याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली आयोजित हुई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया था। आरोप है कि रैली के बाद कुछ लोगों ने मैदान में कथित रूप से 'शुद्धिकरण' किया। याचिका में घटना की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने स्पष्ट किया कि याचिका का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराना है। सरकार ने बताया- दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस की जांच जारी है। सरकार ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

याचिकाकर्ता की ओर से इस आरोप से इनकार किया गया। वकील ने कहा कि याचिका में केवल घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

हार्दिक माहिका शर्मा संग रोमांटिक अंदाज में, तस्वीरों ने जीता दिल

मुंबई ।

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या अपनी निजी जिंदगी में खुशियों भरा जीवन जी रहे हैं। मुश्किलों से उबरने के बाद वे अपनी नई लेडी लव माहिका शर्मा के साथ रोमांटिक पलों का आनंद ले रहे हैं। हार्दिक ने माहिका संग कई रोमांटिक तस्वीरें साझा की हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और फैंस का ध्यान खींच रही हैं। इन तस्वीरों में कपल को एक-दूसरे का हाथ थामे पोज देते देखा जा सकता है, जहां वे मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। मार्मिक पल में हार्दिक अपनी स्वीटहार्ट माहिका की गोद में लेटे हुए बेहद सुकून में दिखे, वहीं माहिका उनके बालों को सहलाती नजर आईं। दोनों की केमिस्ट्री और प्यार एक-दूसरे की बांहों में साफ झलक रहा था।

अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर हार्दिक और माहिका ने साथ में ड्राइव का भी लुत्फ उठाया, जहां वे लाल रंग के आउटफिट में टि्वनिंग करते दिखे। हार्दिक ने इस दौरान अपना शर्टलेस और बाल्ड लुक भी फ्लॉन्ट किया, जिसने उनकी फीमेल फैंस की धड़कनों को तेज कर दिया। हार्दिक की ये नई तस्वीरें उनके फैंस के बीच खूब वायरल हो रही हैं।

रैंप पर उतरे पीएम मोदी, जेन-जी से मिलाया हाथ; बोले - युवा ही लिखेंगे विकसित भारत की नई कहानी

वडोदरा में 'नमो फॉर विकसित भारत' का भव्य आयोजन; हजारों युवाओं से सीधा संवाद, एआई और इनोवेशन पर दिया जोर

35 हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात; फेट कॉरिडोर पूरा, बुलेट ट्रेन पर भी बड़ा ऐलान 'नाराज फूफाजी' वाले तंज से विपक्ष पर निशाना; वडोदरा से मांगा स्वच्छता का वचन

वडोदरा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा दौरे के दौरान आयोजित 'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम ने युवाओं के बीच खास उत्साह पैदा किया। एम.एस. यूनिवर्सिटी के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों, युवा प्रोफेशनल्स और बड़ी संख्या में जेन-जी' युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह खचाखच भर गया और क्षमता पूरी होने के बाद सुरक्षा एवं व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड के प्रवेश द्वार बंद करने पड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हाथों में प्लेकार्ड और रचनात्मक स्लोगन लिए युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी युवाओं से सीधे जुड़ने का अनोखा अंदाज अपनाया। मंच से नीचे उतरकर उन्होंने विशेष रूप से तैयार किए गए युवा पाथवे पर रैंप वॉक किया और दोनों ओर खड़े युवाओं से हाथ मिलाते हुए हाई-फाइव किया।

कार्यक्रम की एक खास झलक उस समय देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्टफोन हाथ में लेकर युवा अंदाज में 'हेलो फ्रेंड्स' संबोधन के साथ सेल्फी वीडियो बनाया। इस दौरान पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एआई में महारत हासिल करें युवा, तकनीक के सिर्फ उपभोक्ता नहीं निर्माता बनें युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी तकनीक और इनोवेशन की सदी है। भारत के युवाओं में दुनिया को नई दिशा देने की क्षमता है। उन्होंने विद्यार्थियों और युवा इंजीनियरों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में दक्षता हासिल करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय युवा केवल नई तकनीकों के उपभोक्ता बनकर न रहें, बल्कि टेक्नोलॉजी के निर्माता और इनोवेटर बनें। उन्होंने युवाओं को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी प्रशासन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एआई आधारित स्थानीय स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तकनीक का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ेगा। ऐसे में भारत को अपनी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को और मजबूत करना होगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि नई

तकनीक का इस्तेमाल देशहित और मानव कल्याण के लिए सकारात्मक तरीके से किया जाए। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ स्किल होना भी जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी सोच को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा से गुजरात के लिए 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न बुनियादी ढांचा एवं जनहितकारी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बड़ोदरा से विकास की नई रेल, गुजरात की धरती से देश को नई रफ्तार

प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्थानों से मालगाड़ी सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। न्यू सानंद (उत्तर), न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाँव और न्यू जेएनपीए से मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत पश्चिमी भारत के औद्योगिक और व्यापारिक नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उद्योगों को माल की तेज आवाजाही का विकल्प मिलेगा और बंदरगाहों से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती मिल सकती है।रेल विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यात्री सुविधाओं और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने बड़ोदरा और टांडा रोड के बीच नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई।

(लेखक-विनोद सिंह 'तकियावाला')

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने गृह राज्य गुजरात की धरती बड़ोदरा से देश के बुनियादी ढाँचे और रेल कनेक्टिविटी के विकास का एक नया अध्याय जोड़ा। बड़ोदरा में आयोजित कार्यक्रम में 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें रेल, माल ढुलाई, सड़क, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएँ शामिल हैं।बड़ोदरा की धरती से होने वाला यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कड़ी देश के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने इसके तीन महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। कुल 326 रूट किलोमीटर लंबे इन खंडों को 20,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इनमें सानंद (उत्तर)-मकरपुरा, न्यू उमरगाँव-न्यू सफाले तथा न्यू सफाले-जेएनपीए खंड शामिल हैं। इन खंडों के राष्ट्र को समर्पित होने के साथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा नेटवर्क परिचालन में आ गया है।

यह उपलब्धि केवल रेलवे की नई पटरियों के विस्तार की कहानी नहीं है। यह देश की अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को नई गति देने वाली आधारभूत संरचना है। मालगाड़ियों के लिए अलग समर्पित कॉरिडोर उपलब्ध होने से माल परिवहन की गति बढ़ेगी, ट्रांजिट टाइम कम होगा और औद्योगिक क्षेत्रों तथा बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जेएनपीए तक सीधी कनेक्टिविटी से आयात- निर्यात के माल की आवाजाही अधिक सुगम होने के साथ लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूर्ण होने को देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे विकसित भारत की यात्रा से जोड़ा। उन्होंने आधुनिक बुनियादी ढाँचे को देश की आर्थिक प्रगति की आधारशिला बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सड़क, रेल, बंदरगाह और अन्य आधारभूत सुविधाओं का तेज विस्तार आवश्यक है। उनके संबोधन में गुजरात के विकास को देश के विकास से जोड़ने और विकास की गति को और तेज करने का संदेश भी स्पष्ट दिखाई दिया।

भारत जैसे विशाल देश में आर्थिक विकास की गति केवल उत्पादन बढ़ाने से निर्धारित नहीं होती। उत्पादन को बाजार तक पहुँचाने की गति, कच्चे माल को उद्योग तक पहुँचाने की क्षमता और बंदरगाहों से देश के अलग-अलग हिस्सों तक माल पहुँचाने की दक्षता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत के बदलते लॉजिस्टिक्स तंत्र की रीढ़ बनने की क्षमता रखता है।

प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्थानों से मालगाड़ी सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई। न्यू सानंद (उत्तर), न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाँव और न्यू जेएनपीए से मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत पश्चिमी भारत के औद्योगिक और व्यापारिक नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे उद्योगों को माल की तेज आवाजाही का विकल्प मिलेगा और बंदरगाहों से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती मिल सकती है।रेल विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यात्री सुविधाओं और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने बड़ोदरा और टांडा रोड के बीच नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इससे बड़ोदरा के साथ छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जैसे क्षेत्रों के लोगों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध होने की उम्मीद है। वहीं छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित जोबट-टांडा रोड नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

यह रेल लाइन अलीराजपुर के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। रेल संपर्क किसी क्षेत्र के लिए केवल आवागमन का साधन नहीं होता, बल्कि उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और पर्यटन की संभावनाएँ भी आगे बढ़ती हैं। ऐसे क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देना उन्हें आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बड़ोदरा से आज केवल तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं हुआ, बल्कि भविष्य की रेल क्षमता बढ़ाने की नींव भी रखी गई। प्रधानमंत्री ने लगभग 329 किलोमीटर लंबी तीन रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन पर 9,700 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इनमें वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी रेल लाइन, मियागाम करजन-चोरंडा-मालसर गेज परिवर्तन तथा विश्वामित्री-दभोई डबलिंग परियोजना शामिल हैं।

वडोदरा-रतलाम के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का विस्तार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला यह रेल मार्ग यात्री तथा माल परिवहन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त रेल लाइनें बनने से मार्ग की क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों के संचालन में सुविधा होगी और बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। विकास के साथ जब यात्री और माल परिवहन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही हो, तब रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना समय की आवश्यकता बन जाता है।

सड़क परिवहन को भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,780 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें एनएच-48 के कामरेज-चलथान खंड का छह लेन में विस्तार, वडोदरा-सूरत खंड में तापी और नर्मदा पर प्रमुख पुलों सहित अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण तथा एनएच-53 पर अभवा, मिंधोला और खजोद जंक्शन पर ग्रेड-सेपरेटेड संरचनाओं का निर्माण शामिल है।

रेल और सड़क—दोनों क्षेत्रों में एक साथ हो रहा यह विस्तार बताता है कि आधुनिक भारत में कनेक्टिविटी को विकास की बुनियादी शर्त माना जा रहा है। किसी उद्योग को बाजार से जोड़ना हो, किसी बंदरगाह को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना हो या किसी दूरदराज गाँव और आदिवासी क्षेत्र को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ना हो, मजबूत परिवहन नेटवर्क उसकी पहली आवश्यकता है।

गुजरात की धरती से इन परियोजनाओं का शुभारम्भ अपने आप में विशेष संदेश देता है। गुजरात लंबे समय से उद्योग, बंदरगाह, व्यापार और निवेश के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। ऐसे में राज्य में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने का प्रभाव केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिमी भारत के व्यापक औद्योगिक और व्यापारिक तंत्र पर पड़ेगा।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से बंदरगाहों तक माल की तेज आवाजाही, औद्योगिक केंद्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स लागत में संभावित कमी भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने में सहायक हो सकती है। यही कारण है कि बड़ोदरा से शुरू होने वाली इन परियोजनाओं को केवल क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसका संबंध देश की अर्थव्यवस्था, निर्यात क्षमता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका से भी जुड़ा है।

बड़ोदरा की धरती आज एक ऐसे विकास मॉडल की साक्षी बनी है, जिसमें रेलवे की नई पटरी केवल शहरों और राज्यों को नहीं जोड़ती, बल्कि उद्योग और बाजार को, बंदरगाह और उत्पादन केंद्र को तथा गाँव और महानगर को एक-दूसरे से जोड़ती है।

प्रधानमंत्री के संबोधन का व्यापक संदेश भी इसी दिशा में रहा कि विकसित भारत का संकल्प मजबूत बुनियादी ढाँचे के बिना पूरा नहीं हो सकता। नई रेल लाइनें, समर्पित माल ढुलाई गलियारे, आधुनिक राजमार्ग और बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मिलकर देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने का आधार तैयार करते हैं।

आज बड़ोदरा से विकास की जो नई रेल चली है, उसकी मंजिल केवल गुजरात नहीं है। इसकी दिशा पूरे देश की आर्थिक रफ्तार, बेहतर कनेक्टिविटी और विकसित भारत के उस संकल्प की ओर है, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढाँचा आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आधार बनेगा। गुजरात की धरती से शुरू हुआ यह विकास का सफर देश की विकास यात्रा को नई गति देने की क्षमता रखता है।

(विनोद सिंह 'तकियावाला', स्वतंत्र पत्रकार व स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

जानलेवा हॉस्टल

दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के निकट स्थित पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना में मरने वाले छात्रों की संख्या सोमवार को सात घोषित की गई। अभी कुछ और छात्रों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। कुंभकरणी नींद में सोई हुई राज्य सरकार अब जागी है। राजस्थान पहुंचकर पुलिस ने फरार हॉस्टल मालिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार दिखाया है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, भवन के रखरखाव में लापरवाही बरतने और दूसरों की सुरक्षा खतरे में डालने के आरोप दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री के निर्देश पर पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन के उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता,सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने रविवार रात हुई घटना की मजिस्ट्रेटी जांच करने के भी आदेश दिए हैं। सवाल उठता है कि किसी जानलेवा हादसे के बाद ही ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पहले ही बेगुनाह लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले भवनों की जांच करके मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिनका दायित्व रिहाइशी भवनों व्यावसायिक भवनों में बदलने की जांच करना होता है? इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी से सहमत हुआ जा सकता है, जो उसने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सोमवार की सुनवाई के दौरान की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस हादसे के लिये सिर्फ भवन मालिक ही नहीं, बल्कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों के लिये रहने के लिये जरूरी सुविधा देने में विफल रहा है। जिसके कारण छात्रों को निजी पेइंग गेस्ट यानी पीजी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। अदालत ने संबंधित विभागों को दस दिनों के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह दुखदायक ही कहा जाएगा कि दिल्ली में पालम, विवेक विहार, साकेत, मालवीय नगर के बाद अब सत्य निकेतन का दुखद हादसा सामने आया है। यह दुखद ही है कि दिल्ली में लगातार हो रहे हादसों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में एक बात समान है -बेगुनाहों की मौत और असुरक्षित इमारतें, बिना मंजूरी के बदलाव, रिहायशी प्रॉपर्टी का व्यावसायिक इस्तेमाल और सबसे चिंताजनक नियम-कानून लागू करने में तंत्र की नाकामी। यह विडंबना ही है कि समाज में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा कमाने की हवस इस हद तक बढ़ गई है कि वे किसी के जीवन व मृत्यु की भी परवाह नहीं करते। दूरदराज के राज्यों से अपने सुनहरे सपने लेकर दिल्ली आने वाले छात्र मजबूरी में मुंहमांगे दाम देकर अमानवीय स्थिति वाले पीजी में रहने को मजबूर हो जाते हैं। जब जर्जर इमारतों की स्थिति को नजरअंदाज करके चलताऊ निर्माण कार्य कराये जाते हैं तो हादसे का होना तय हो जाता है। हादसे का शिकार हुई सत्य निकेतन बिल्डिंग के लिये ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल बनाने की अनुमति मिली थी। लेकिन नये प्लान की मंजूरी लिए बिना इसे पांच मंजिला बना दिया गया। क्या किसी एमसीडी के अधिकारी की नजर इस अवैध निर्माण पर नहीं गई होगी? जब दशकों पुरानी यह इमारत जमींदोज हुई तो तब कथित तौर पर इसमें अवैध रूप से रेनोवेशन का काम चल रहा था। देश की राजधानी में नियामक कानूनों या बिल्डिंग कोड की कमी नहीं है।

दो टूक- मौत का इंतजार करती इमारतें और गहरी नींद सोता प्रशासन

(लेखक- योगेश कुमार गोयल)

- जर्जर इमारतों से ज्यादा जर्जर है निगरानी का सिस्टम

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में जो हृदयविदारक घटना घटित हुई है, वह केवल एक पांच मंजिला इमारत के भरभराकर गिरने की घटना नहीं बल्कि राजधानी की उस व्यवस्था का ढ़हना है, जिसकी नींव नागरिकों की सुरक्षा, कानून के शासन और प्रशासनिक जवाबदेही पर टिकी होनी चाहिए थी। जिस इमारत में कुछ घंटे पहले तक देश के अलग-अलग हिस्सों से आए युवा अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे, देखते ही देखते वह ईंट, सीमेंट और लोहे के मलबे में बदल गई। धूल का गुबार तो छंट जाएगा, मलबा भी हट जाएगा, सड़कें फिर सामान्य हो जाएंगी लेकिन उन परिवारों के जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है, वह कभी नहीं भर सकेगा। 'हॉस्टल डेज' नामक लड़कों के लिए बने पीजी की इस पांच मंजिला इमारत में हादसे के वक्त कई छात्र अपने कमरों में थे, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इमारत लगभग 40-50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय बेसमेंट में मरम्मत तथा खुदाई का काम चल रहा था। यही तथ्य इस त्रासदी को और भयावह बना देता है।

सवाल केवल यह नहीं है कि इमारत क्यों गिरी बल्कि असली सवाल यह है कि इतनी पुरानी और संवेदनशील इमारत में बेसमेंट की खुदाई और निर्माण संबंधी गतिविधियां आखिर चल कैसे रही थी? हर बड़े भवन हादसे के बाद एक ही कहानी दोहराई जाती है। प्रशासन कहता है कि जांच होगी, कुछ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है और कुछ दिनों बाद पूरा मामला फाइलों के नीचे दब जाता है। फिर किसी दूसरे इलाके में कोई और इमारत गिरती है, कहीं आग लगती है, कोई बेसमेंट मौत का कुआं बन जाता है और हम फिर वही प्रश्न पूछते रह जाते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? सच तो यह है कि भारत के शहरों में कोई बहुमंजिला अवैध निर्माण रातों-रात खड़ा नहीं होता। जमीन का उपयोग बदलता है, नक्शा बनता है, निर्माण शुरू होता है, मंजिलें बढ़ती हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन मिलते हैं और अंततः उस इमारत में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक विभागों और अधिकारियों की भूमिका होती है। ऐसे में यह कहना कि प्रशासन को कुछ पता ही नहीं था, जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान बहाना है।

यदि कोई इमारत नियमों के विरुद्ध बन रही थी तो निर्माण के दौरान संबंधित नगर निगम अधिकारी कहां थे? यदि वहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी तो फायर विभाग ने सुरक्षा का आकलन क्यों नहीं किया? बिजली और पानी के कनेक्शन किस आधार पर मिले? पुलिस और स्थानीय प्रशासन की नजर उस भवन पर क्यों नहीं पड़ी? और यदि सब कुछ नियमों के अनुसार था तो फिर हादसा हुआ कैसे? यही वे प्रश्न हैं, जिनका जवाब केवल ठेकेदार या किसी छोटे कर्मचारी को दोषी ठहराकर नहीं दिया जा सकता। सत्य निकेतन की त्रासदी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि दिल्ली में पीजी संस्कृति तेजी से बढ़ी है। देशभर से राजधानी में पढ़ने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और रोजगार तलाशने आने वाले हजारों युवा ऐसी इमारतों में रहते हैं, जहां कमरे छोटे हैं, गलियां संकरी हैं, सीढ़ियां संकरी हैं और सुरक्षा मानकों की स्थिति अक्सर संदिग्ध रहती है। मकान मालिक के लिए कमरों की संख्या बढ़ाना कारोबार है लेकिन उस कमरे में रहने वाला छात्र अपने सपने लेकर वहां आता है। जब छह कमरों की अनुमति वाली इमारत में 25 से अधिक कमरे बना दिए जाते हैं, जब बेसमेंट को पार्किंग के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब एक ही निकास मार्ग पर सैकड़ों लोगों की सुरक्षा निर्भर कर दी जाती है, तब यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं रहता, यह मानव जीवन के साथ खिलवाड़ बन जाता है। दिल्ली में अतीत की त्रासदियां भी हमें बार-बार चेताती रही हैं। 1997 का उपहार सिनेमा अग्निकांड हो या हाल के वर्षों में सामने आए बेसमेंट, कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक इमारतों से जुड़े हादसे, हर घटना के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे। बंद दरवाजे, अवरुद्ध निकास, अवैध निर्माण, अग्निशमन उपकरणों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक उदासीनता बार-बार त्रासदियों की पृष्ठभूमि में दिखाई देती रही है। फिर भी व्यवस्था की स्मृति इतनी कमजोर है कि कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर पुराने ढ़र्रे पर लौट आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सस्पेंशन हमेशा छोटे कर्मचारी का ही क्यों होता है? यदि किसी इलाके में वर्षों तक अवैध निर्माण चलता रहा, यदि नियमों के विपरीत इमारतें खड़ी होती रही और उनमें पीजी, कोचिंग सेंटर, दुकानें या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलती रही तो उस पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिसने इसे होने दिया। तत्कालीन अवैध निर्माण प्रभारी, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, जोनल स्तर के जिम्मेदार अधिकारी और संबंधित विभागों की भूमिका की निष्पक्ष जांच क्यों न हो? यदि मिलीभगत प्रमाणित होती है तो कार्रवाई भी उसी अनुपात में कठोर क्यों न हो?

समस्या किसी एक इमारत की नहीं है। दिल्ली और देश के तमाम शहरों में हजारों ऐसी इमारतें हैं, जो बाहर से सामान्य दिखाई देती हैं लेकिन भीतर से मौत के जाल में बदल चुकी हैं। कहीं बेसमेंट में अवैध निर्माण है, कहीं बिना वेंटिलेशन के कोचिंग सेंटर, कहीं संकरी सीढ़ियां, कहीं बंद खिड़कियां, कहीं लोहे की ग्रिलें और कहीं एक ही प्रवेश-निकास द्वार। अग्निशमन उपकरण कई जगह केवल निरीक्षण के समय दिखाने के लिए रखे जाते हैं और आपातकालीन निकास कागजों पर मौजूद रहते हैं, वास्तविकता में नहीं। ऐसी स्थिति में हादसा होने पर दमकल की गाड़ियां भी संकरी गलियों में फंस जाती हैं। बचाव दल के पास पहुंचने का रास्ता नहीं होता और अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। फिर कुछ ही मिनटों में एक इमारत कब्रिस्तान में बदल जाती है।

अब जरूरत केवल दोषी खोजने की नहीं, व्यवस्था बदलने की है। दिल्ली की सभी पुरानी बहुमंजिला और व्यावसायिक इमारतों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। पीजी, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर और बेसमेंट में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अनिवार्य जांच होनी चाहिए। फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध हो। अवैध निर्माण पर केवल जुर्माना लगाकर उसे वैध बनाने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। गंभीर उल्लंघन वाली इमारतों को तत्काल सील और आवश्यकतानुसार ध्वस्त किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि जिम्मेदारी ऊपर तक जानी चाहिए। किसी दुर्घटना के बाद दो-चार छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर देना प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, अक्सर जिम्मेदारी से बचने का तरीका बन जाता है। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही, मिलीभगत या भ्रष्ट आचरण के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ी है तो उसके विरुद्ध कठोर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए।

चिंतन मनन

प्रेम और समर्पण

प्रेम जीवन की परम समाधि है. प्रेम ही शिखर है जीवन ऊर्जा का. वही गौरीशंकर है जिसने प्रेम को जाना, उसने सब जान लिया. जो प्रेम से वंचित रह गया, वह सभी कुछ से वंचित रह गया। प्रेम की भाषा को ठीक से समझ लेना जरूरी है। प्रेम के शास्त्र को ठीक से समझ लेना जरूरी है। क्योंकि प्रेम ही तीर्थयात्रा है। उससे ही पहुंचने वाले पहुंचे हैं और जो नहीं पहुंचे, वे इसलिए नहीं पहुंचे कि उन्होंने जीवन को कोई और रंग दे दिया, जो प्रेम का नहीं था। प्रेम का अर्थ है, समर्पण की दशा, जहां दो मिटते हैं, एक बचता है। जहां प्रेमी और प्रेम पात्र अपनी सीमाएं खो देते हैं, जहां उनकी दूरी समग्र रूपेण शून्य हो जाती है। यह उचित नहीं कि प्रेमी और प्रेम-पात्र करीब आ जाते है; क्योंकि करीब होना भी दूरी है। पास नहीं आते खो जाते हैं। निकटता में भी तो फासला है। प्रेम उतना फासला भी बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम दो को एक बना देता है। प्रेम अद्वैत है। इस प्रेम को हम थोड़ा समझें। ऐसा तो व्यक्ति ही खोजना कठिन है, जिसने प्रेम न किया हो। गलत ढंग से किया हो, गलत प्रेम पात्र से किया हो, लेकिन प्रेम किये बिना तो कोई बच नहीं सकता क्योंकि वह तो जीवन की सहज अभिव्यक्ति है। तो तीन तरह के प्रेम हैं। समझ लें। पहला जिसमें सौ में से निन्यानबे लोग उलझ जाते हैं। वह वस्तुओ का प्रेम है- धन का, संपदा का, मकान का, तिजोरियों का। वस्तुओ का प्रेम- प्रेम के लिए सबसे बड़ा धोखा है लेकिन उसमें कुछ खूबी है; इसलिए सौ में से निन्यानबे लोग उसमें पड़ जाते हैं और वह खूबी यह है कि वस्तुओं के प्रति तुम्हें समर्पण नहीं करना पड़ता। वस्तुओं को तुम अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। तुम्हारी कार, तुम्हारी कार है। तुम्हारा मकान, तुम्हारा मकान है। तुम समर्पित होने से बच जाते हो। और तुम्हें यह अहसास होता है, कि वस्तुएं तुम्हारे प्रति समर्पित हैं। एक तरह का अद्वैत सध जाता है।

तुम हाथ में रुपया रखे हो। रुपये की सीमा और तुम्हारी सीमा मिट गई। रुपया बाधा नहीं डालता सीमा के मिटने में और तुम्हें समर्पण करने के लिए मजबूर नहीं करता। रुपया समर्पित है। तुम जो चाहो करो, रुपया ना-नुकुर नहीं करेगा। तुम चाहे नदी में फेंक दो, तुम चाहे भिखारी को दे दो, तुम चाहे कुछ सामान खरीद लो, तुम चाहे तिजोरी में संभाल कर रखो। रुपयें की कोई अपनी मनोदशा नहीं है। रुपया पूरा समर्पित है।

विचार मंथन

हर हादसे के बाद कोई बख्शा नहीं जाएगा का जुमला

(लेखक- सनत जैन)

जब भी कोई बड़ा हादसा होता है या कोई ऐसा अपराध होता है जिससे सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, उस समय पर भाजपा नेताओं के जो बयान आते हैं उसमें कहा जाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। लेकिन यह एक जुमला है जो भाजपा शासित राज्यों में और भाजपा के नेताओं द्वारा पिछले कई सालों से बोला जा रहा है। कार्यवाही के नाम पर 9 दिन चले अढाई कोस की स्थिति बनी रहती है। जांच के नाम पर बड़े-बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन ना तो कभी जाँच रिपोर्ट सामने आती है ना ही किसी अपराधी को सजा मिलती हुई दिखती है। ताबड़तोड़ तरीके से बड़ी-बड़ी कार्यवाही दिखावे के लिए हो जाती है, लेकिन असल में होता-जाता कुछ नहीं है। मामले को शांत करने के लिए हर दुर्घटना, हादसे और अपराध में सरकारी खजाने से मुआवजा देकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। इसे कहते हैं हर्र लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। सरकारी खजाने से मुआवजा देकर भाजपा नेता वाहवाही लूट लेते हैं। मामला भी शांत हो जाता है, जांच के बहाने मामला महीनों और सालों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाता है। पिछले एक दशक से यही सब देखने को मिल रहा है। आम जनता को दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार और घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से जान और माल से हाथ धोना पड़ता है। यह घटना लगातार चलती रहती है। घटना हो जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं आता है। जो दावे नेता और अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं वह केवल बयान तक सीमित रहते हैं।

दिल्ली में हाल ही में जो इमारत गिरी है, इसमें सात की मौत हो गई है। करीब एक दर्जन घायल छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। पूरी दिल्ली में इस तरह के निर्माण हज़ारों की संख्या में है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। पिछले कई वर्षों से नगर निगम दिल्ली में भाजपा काबिज है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी भाजपा की है। एलजी भी भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले भी दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार जुमला यही रहता है हम किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। कुछ दिनों तक मामला बयानों से सुर्खियों में बना रहता है। सरकारी खजाने से मुआवजा देने के बाद जैसे ही यह मामला शांत पड़ता है उसके बाद सरकार, दिल्ली नगर निगम और केंद्र सरकार सब कुंभकर्णी निद्रा में चले जाते हैं। अधिकारी, पार्षद, विधायक, मंत्री, पुलिस सब अपना अपना सुविधा शुल्क लेकर आंख बंद करके बैठे रहते हैं। किसी भी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जाती है। उसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होती है। जिसके कारण घटना के बाद एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। जांच चलती रहती है, निष्कर्ष कभी नहीं निकलता है। दोषी, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, अधिकारी, कर्मचारी और राजनेता हमेशा बचे रहते हैं। मामला न्यायपालिका के पास जाता है। न्यायपालिका भी दोषी अधिकारियों पर कभी कोई ऐसी दंडात्मक कार्यवाही नहीं करती है जिसके कारण अधिकारियों में कोई खौफ हो। दिल्ली में ऐसे हजारों निर्माण हैं, जो अवैध रूप से किए गए हैं। यह सब सामने दिखते हैं, लेकिन रिश्वत और भ्रष्टाचार में सभी की हिस्सेदारी होती है। यह काम अनवरत चल रहा है।

सरकार और अधिकारियों को मालूम है, जब कोई घटना होगी उससे हमें कैसे निपटना है। भ्रष्टाचार और रिश्वत की कमाई इतनी बड़ी है कि इसकी छत्रछाया में आकर ईमानदार से ईमानदार अधिकारी और नेता भी अपने आपको इस व्यवस्था में ढाल लेता है। सबका अपना अपना भाग्य है, जो मर गए या जिन्हें नुकसान हुआ उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होते हैं। उनका भाग्य जिम्मेदार होता है। अधिकारी और नेता कर भी क्या सकते हैं। यही कहा जा सकता है। राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने भी इसी तरह से कहा था। जांच कर रहे हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। छोटे-मोटे कर्मचारियों को जेल भेजकर अब सारे मामले में पर्दा डाला जा रहा है। यह सारा देश देख रहा है। आम लोगों के बीच अब यह चर्चा होने लगी है। भाजपा नेता और डबल इंजन की सरकारों में दावे बहुत बड़े-बड़े किए जाते हैं, लेकिन वह दावे केवल अखबारों और मीडिया की सुर्खियों के लिए होते हैं। जिसके कारण अब आम जनता में भी जगह-जगह रोष देखने को मिलने लगा है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नोएडा के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को गलत तरीके से आंदोलनकारी छात्रा को एनएसए में 5 महीने की हिरासत में रखा था, पर हाईकोर्ट ने 500000 रूपये का जुर्माना अधिकारियों से वसूल करने का आदेश दिया है। यदि इसी तरह के आदेश न्यायपालिका की ओर से आने लगे, दोषी अधिकारियों कर्मचारियों और पद पर बैठे हुए संवैधानिक पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय होने लगे। सरकारी खजाने से पैसा बांटने के स्थान पर यदि दोषी अधिकारियों से वसूली की जाने लगे तो इस तरह के अवैध कार्यों और अवैध निर्माणों पर रोक लग सकती है। अभी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण तथा किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होने से जिसकी मर्जी जो आ रहा है वह कर रहा है। जिसके कारण हर जगह अराजकता की स्थिति बनती चली जा रही है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सोना 544 चढ़ा, चांदी में भी 993 का उछाल

एमसीएक्स पर सोना 600 से अधिक महंगा, चांदी में 1600 रुपए से ज्यादा की बढ़त

नई दिल्ली ।

वैश्विक तनाव और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते मंगलवार को सोने और चांदी के दाम में जोरदार तेजी देखने को मिली। मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी और तकनीकी शॉर्ट कवरिंग ने इन कीमती धातुओं को मजबूत समर्थन दिया। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर खबर लिखे जाने तक सोने का अक्टूबर अनुबंध 639 रुपये की बढ़त के साथ 1,53,457 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह चांदी का दिसंबर अनुबंध 1,664 रुपये की जोरदार उछाल के साथ 2,40,680 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर भी कीमती धातुओं में चमक जारी रही। सोना 3.20 डॉलर की तेजी के साथ 4,479.80 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, वहीं चांदी 0.88 डॉलर की बढ़त के साथ 67.63 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और तकनीकी स्तर पर शॉर्ट कवरिंग कीमतों को लगातार मजबूती प्रदान कर रही है।

दीपा ज्वेलर्स का शेयर 25 प्रतिशत की बढ़त के साथ सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।

दीपा ज्वेलर्स लिमिटेड का शेयर 177 रुपये के अपने निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत की बढ़त के साथ मंगलवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर शेयर ने 221.05 रुपये पर कारोबार शुरू किया जो निर्गम मूल्य से 24.88 प्रतिशत अधिक है। एनएसई पर यह 24.85 प्रतिशत की बढ़त के साथ 221 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1,920.56 करोड़ रुपये रहा। दीपा ज्वेलर्स के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बोली के अंतिम दिन करीब 43 गुना अभिदान मिला था।कंपनी के 460 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 168-177 रुपये प्रति शेयर था। दीपा ज्वेलर्स नए शेयर जारी कर जुटाई गई राशि का इस्तेमाल खरीद, रखरखाव सहित दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कामकाज के लिए करेगी।वर्ष 2016 में स्थापित कंपनी संगठित क्षेत्र में कारोबार करने वाली व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी)आधार पर डिजाइनर, प्रसंस्करणकर्ता और हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की आपूर्तिकर्ता है। मुख्य तौर पर इसका कारोबार तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरलम में फैला है।

चीन का निर्यात अगस्त में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ा

- व्यापार अधिशेष भी बढ़कर 119.1 अरब डॉलर हुआ

बैंकॉक।

सीमा शुल्क एजेंसी के मुताबिक, अगस्त में चीन का व्यापार अधिशेष 119.1 अरब डॉलर रहा, जो जुलाई के 112.5 अरब डॉलर से अधिक है। मोटर वाहन और उच्च प्रौद्योगिकी वाले सामान की मजबूत मांग से निर्यात 23.9 फीसदी बढ़ा, जिसने वैश्विक नीति-निर्माताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह लगातार बढ़ता अधिशेष अमेरिका और अन्य देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगस्त में आयात भी 28.2 फीसदी बढ़ा। वाहनों का निर्यात 43 फीसदी और सेमीकंडक्टर का 129.8 फीसदी बढ़ा, जो मजबूत वैश्विक मांग को दर्शाता है। इससे चीन का व्यापार अधिशेष इस साल रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि, चीन का कहना है कि उसका व्यापार अधिशेष को अधिकतम करने का कोई लक्ष्य नहीं है। अमेरिका को चीन का निर्यात 34.4 फीसदी बढ़कर 42.5 अरब डॉलर हुआ, जिससे चीन के पक्ष में 29.2 अरब डॉलर का अधिशेष रहा। यूरोपीय संघ को निर्यात 6.6 फीसदी, दक्षिण-पूर्व एशिया को 30.2 फीसदी और लातिन अमेरिका को 17.5 फीसदी बढ़ा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल व्यापार अधिशेष एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। हालांकि, घरेलू स्तर पर चीन अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संघर्षरत है।

कनोहर इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ 2 रूपये के शेयर की 632 कीमत? निवेश कितना सुरक्षित?

मुंबई।

कनोहर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का करीब 1,055.74 करोड़ रुपए का आईपीओ 8 सितंबर से 10 सितंबर तक खुला है। कंपनी ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर का प्राइस बैंड 601 से 632 रुपए तय किया है। यानी ऊपरी कीमत पर निवेशक फेस वैल्यू से 316 गुना कीमत चुकाना पड़ेगा। न्यूनतम 23 शेयरों की एक लॉट के लिए निवेशक को न्यूनतम 14,536 रुपए निवेश करने होंगे।

सवाल यह है, क्या इतनी ऊंची कीमत निवेशकों के लिए सुरक्षित है? फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस मे इतना अंतर क्यों है। कंपनी सपने दिखाकर निवेशकों से ज्यादा पैसे निवेश करा रही है। आईपीओ का मूल्यांकन कंपनी की कमाई, संपत्ति, भविष्य की संभावनाओं और बाजार में समान कंपनियों के मूल्यांकन के आधार पर किये जाने का दावा किया जाता है। 632 रुपए की कीमत पर निवेशकों को जोखिमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

कंपनी के वित्तीय आंकड़े पहली नजर में मजबूत दिखाई देते हैं। वित्त वर्ष 2024 में 281.12 करोड़ रुपए का राजस्व और मात्र 17.76 करोड़ रुपए का मुनाफा था, जो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर करीब 662.86 करोड़ और मुनाफा 129.73 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी पर कर्ज करीब 39 करोड़ रुपए है। इशू लाने के पहले और बैलेंस शीट में मुनाफा और कारोबार बढ़कर दिखाया जाता है। इस तरह की धारणा बनी हुई है।

कंपनी के शेयर का मूल्यांकन महंगा है। ऊपरी प्राइस बैंड पर पोस्ट-इश्यू पी/ई करीब 38.6 गुना बैठता है। कंपनी का वित्त वर्ष 2026 का ईपीएस करीब 17.43 रुपए और नेट एसेट मात्र 50.09 रुपए बताई गई है। यानी निवेशक बुक वैल्यू की तुलना में काफी ऊंची कीमत वसूल की जा रही है।एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के राजस्व का करीब 85त्न हिस्सा सरकारी संस्थाओं से आया। सरकारी ऑर्डर, भुगतान में देरी का असर कंपनी के कारोबार पर पड़ सकता है। बड़े प्रोजेक्टों में लागत बढ़ने और मार्जिन घटने का जोखिम भी कंपनी के दस्तावेजों में बताया गया है। कंपनी स्वयं स्वीकार कर रही है कि उसके कारोबार में जोखिम भी बड़ा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,055.74 करोड़ रुपए के इश्यू में केवल 300 करोड़ रुपए कंपनी को नए शेयर जारी करके मिलेंगे। जबकि 755.74 करोड़ रुपए का हिस्सा ऑफर फॉर सेल का है। यानी इश्यू की बड़ी रकम मौजूदा शेयरधारकों के पास जाएगी।

कनोहर इलेक्ट्रिकल्स का कारोबार और हालिया वित्तीय प्रदर्शन पिछले 2 साल में मजबूत जरूर दिखता है।इशूयू लाने के पहले बैलेंस शीट को आकर्षक बनाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है।` 2 के शेर का प्रीमियम 601-632 रुपए का मूल्यांकन उचित प्रतीत नहीं होता । इसलिए केवल आईपीओ के प्रचार, प्रीमियम या ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर निवेश करना, निवेशकों के लिए जोखिम पूर्ण हो सकता है।

नौकरी बाजार में रौनक, अगस्त में दफ्तरों में नियुक्तियां 14 फीसदी बढ़ीं

मोटर वाहन, स्वास्थ्य और खुदरा क्षेत्र ने दिया सहारा

मुंबई

इन्फो एज के एक प्रमुख ब्रांड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दफ्तरों में भर्ती अगस्त 2023 में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढ़कर 3,028 पर पहुंच गई। मोटर वाहन, स्वास्थ्य सेवा और खुदरा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत नियुक्तियों ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में आईटी और गैर-आईटी दोनों क्षेत्रों में सभी अनुभव स्तरों पर नियुक्तियों में तेजी दर्ज की गई। वाहन क्षेत्र में 19 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा में 16 प्रतिशत और खुदरा क्षेत्र में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, बीमा (12 फीसदी), आईटी (11 फीसदी), बैंकिंग और एफएमसीजी (10 फीसदी प्रत्येक) जैसे क्षेत्रों में भी अच्छी वृद्धि देखी गई। हालांकि, आतिथ्य एवं यात्रा और शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। सभी अनुभव स्तरों पर भर्ती बढ़ी, जिसमें नए स्नातकों के लिए 15 प्रतिशत और 13 से 16 वर्ष के अनुभव वाले पेशेवरों के लिए 18 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है। शहरों की बात करें तो हैदराबाद में सर्वाधिक 23 प्रतिशत, कोलकाता में 22 प्रतिशत और चेन्नई में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उभरते शहरों में भुवनेश्वर (32 फीसदी), रायपुर (23 फीसदी) और सूरत (21 फीसदी) में मजबूत वृद्धि देखने को मिली। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस वृद्धि को त्योहारी कैलेंडर में बदलाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल त्योहारों का बड़ा हिस्सा अगस्त में था, जो इस साल सितंबर में स्थानांतरित हो गया है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 555 अंक , निफ्टी 144 अंक गिरा

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से भी बाजार पर दबाव आया है उससे भी ये गिरा है। आज प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों के चलते भी बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना रहा और निवेशकों ने मुनाफावसूली पर जोर दिया। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स, 555 अंक से अधिक की गिरावट के साथ ही 75,577.58 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि, दिन के कारोबार के दौरान इसने 76,012.11 का उच्चतम स्तर भी छुआ था, जो बाजार में अस्थिरता को दर्शाता है। इसी तरह 50 शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 144 अंकों की गिरावट के साथ ही 23,635.10 पर समाप्त हुआ।

कारोबार की शुरुआत में निफ्टी में 23,758.95 तक का उछाल भी देखा था पर वह इस बढ़त को बरकारार नहीं रख सका और अंत में गिरावट के साथ ही लाल निशान में बंद हुआ।आज बाजार पर दबाव बनाने में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सबसे अधिक प्रभाव रहा। पश्चिम एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव में कोई कमी न आने के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और फिलहाल 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें आयातकों और ईंधन पर निर्भर उद्योगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।वहीं घरेलू मोर्चे पर, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में तेज बिकवाली ने भी सूचकांकों को नीचे धकेलने का काम किया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.37 फीसदी टूटकर बंद हुआ, जो इस क्षेत्र के प्रदर्शन में कमजोरी का स्पष्ट संकेत देता है। इसी तरह, निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी 0.54 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिससे वित्तीय शेयरों पर बढ़ते दबाव का पता चलता है। निवेशकों ने इन क्षेत्रों से दूरी बनाते हुए बिकवाली का रुख अपनाया।

निफ्टी 50 में शामिल शेयरों की बात करें तो, कुल 31 शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए, जबकि केवल 17 शेयरों ने बढ़त दर्ज की। जिन प्रमुख शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, उनमें एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई बैंक शामिल रहे, जिनके शेयरों में 2-2 फीसदी तक की कमी आई। इसके अतिरिक्त, एचडीएफसी बैंक और देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के शेयर भी 1 प्रतिशत से अधिक टूटकर बंद हुए, जिससे बाजार की धारणा और कमजोर हुई।

सुजलॉन को अयाना रिन्यूएबल पावर से पवन ऊर्जा परियोजना का मिला ठेका

नई दिल्ली ।

सुजलॉन को अयाना रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से मध्य प्रदेश में 200 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का ठेका मिला है। यह मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कंपनी का तीसरा पवन ऊर्जा ठेका है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के लिम्बावास में उसकी 3.15 मेगावाट क्षमता वाली एस144 पवन टर्बाइन की 64 इकाइयां लगाई जाएंगी। इस ठेके के साथ सुजलॉन के तीन मेगावाट प्लेटफॉर्म ने 10 गीगावाट क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है।

परियोजना से पैदा होने वाली बिजली को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीसीएल) के राज्य ग्रिड से जोड़ा जाएगा। सुजलॉन समूह के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि 150 मीटर की ऊंचाई पर 55 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता के साथ मध्य प्रदेश भारत में पवन ऊर्जा वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख राज्यों में से एक बन सकता है।

उन्होंने कहा कि कंपनी को राज्य में लगातार दो पवन ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके मिले हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है।

अे धिकारी ने कहा` कि यह परियोजना मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी स्थापित करने की दिशा में अयाना के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, हम दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने और भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव में योगदान देने के लिए साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं।

सीएम मोहन यादव की दुबई यात्रा- मध्य प्रदेश को मिला वैश्विक निवेश का भरोसा

- तातारस्तान, इथियोपिया और यूएई ने मध्य प्रदेश में निवेश में दिखाई रुचि

दुबई ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की हालिया दुबई यात्रा मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता लाई है। एआईएम कांग्रेस-2026 में उन्होंने कई देशों के प्रमुखों व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को मजबूती से पेश किया, जिससे वैश्विक स्तर पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा। सोमवार को दुबई में मुख्यमंत्री मोहन यादव और रूस के तातारस्तान गणराज्य के प्रमुख रुस्तम मिन्निखानोव की बैठक में तातारस्तान ने मध्य प्रदेश में निवेश की गहरी इच्छा जताई।

दोनों ने उन्नत विनिर्माण, पेट्रोकेमिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जनवरी 2027 में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन (जीआईएस) के लिए तातारस्तान को आमंत्रित किया, जिस पर सकारात्मक सहमति मिली। द्विपक्षीय व्यापार मिशन और बी2बी व जी2जी साझेदारी पर भी जोर दिया गया।

अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने इथियोपियाई राष्ट्रपति ताये अत्स्के सेलासी को भी जीआईएस 2027 का न्योता दिया और प्रदेश में निवेश के अवसर बताए।

उन्होंने यूएई के शेख सऊद बिन साकर अल कासिमी से भी बातचीत कर निवेशकों को आकर्षित किया।

विश्व बैंक के डिजिटल एवं एआई मामलों के वाइस प्रेसिडेंट सांगबु किम के साथ हुई बैठक में मध्य प्रदेश में डिजिटल विस्तार और एआई गवर्नेंस परियोजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें विश्व बैंक ने फंडिंग में रुचि दिखाई।

यूनिटी स्माल फायनेंस बैंक ने 3 करोड़ से कम की एफडी के लिए बढ़ाईं ब्याज दरें

- एफडी पर दे रहा 8.50 फीसदी तक ब्याज

मुंबई अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित और आकर्षक रिटर्न के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो यू निटी स्माल फायनेंस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर नई और ऊंची ब्याज दरें लागू की हैं। बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी के लिए ये दरें जारी की हैं, जहां सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 8 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 8.50 फीसदी तक का शानदार ब्याज मिल रहा है। ये नई दरें निवेश के लिए एक बेहतरीन मौका पेश करती हैं। बैंक की नई दरों के अनुसार, 501 दिन की विशेष अवधि वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 8 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 8.50 फीसदी का उच्चतम ब्याज मिलेगा। 12 महीने की एफडी पर भी सामान्य ग्राहकों के लिए 7.50 एफडी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 फीसदी ब्याज तय है। छोटी अवधि की एफडी पर भी आकर्षक रिटर्न मिल रहा है। 7 से 45 दिन की जमा पर 4 फीसदी, 61 से 90 दिन पर 5 फीसदी और 165 दिन से 6 महीने तक की अवधि पर 5.50 फीसदी ब्याज उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों को अधिकांश अवधियों पर सामान्य ग्राहकों की तुलना में 0.50 फीसदी अधिक ब्याज का लाभ मिलेगा, जिससे यह बचत का एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है।

यूरोप जाने वाले डीजल कार्गो में करीब 60 फीसदी हिस्सा भारतीय रिफाइनरियों का

-अमेरिका से निर्यात कमजोर होने से भारत डीजल का प्रमुख सप्लायर बना

नई दिल्ली, ।

भारत अब तेल और ईंधन का बड़ा खरीदार नहीं, बल्कि दूसरे देशों को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने वाला एक देश भी बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से डीजल की आपूर्ति में भारी कमी और अमेरिका से निर्यात कमजोर होने के बीच भारत यूरोप के लिए डीजल का एक प्रमुख सप्लायर बनकर उभरा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में बाब-अल-मंदेब समुद्री मार्ग से यूरोप जाने वाले डीजल कार्गो में करीब 60 फीसदी हिस्सा भारतीय रिफाइनरियों का था।इस दौरान करीब 2 लाख बैरल प्रतिदिन डीजल और गैस ऑयल इस मार्ग से यूरोप पहुंचा। खास बात यह है कि मार्च और अप्रैल में इस समुद्री रास्ते से डीजल की आवाजाही रुक गई थी। ऐसे समय में भारतीय रिफाइनरियों ने यूरोप की ईंधन जरूरतों को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाई। भारत की मजबूत स्थिति का सबसे बड़ा कारण उसका विशाल रिफाइनिंग नेटवर्क है। भारत के पास करीब 258.1 मिलियन टन सालाना तेल शोधन क्षमता है। इस क्षमता के कारण भारत घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने करीब 6.15 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया।

यूरोप में इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है। रूस पर प्रतिबंध, कुछ रिफाइनरियों में उत्पादन संबंधी समस्याएं और वैश्विक व्यापार मार्गों में बदलाव के कारण यूरोप को ईंधन के नए स्रोतों की जरूरत पड़ रही है।

यूरोप के डीजल बाजार में रूस लंबे समय तक एक बड़ा सप्लायर रहा है, लेकिन अब रूस से होने वाले समुद्री डीजल और गैसऑयल निर्यात में काफी कमी आई है।

पेट्रोलियम कंपनियों ने सरकार से मांगे 75 हजार करोड सरकार का फैसला 2027 में

नई दिल्ली देश की तीन बड़ी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ईंधन बिक्री में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 75 हजार करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। सरकार ने फिलहाल फैसला टालते हुए नुकसान का आकलन कर 2027 में मुआवजे पर निर्णय लेने की बात कही है। दिलचस्प यह है, इन कंपनियों के पिछले दो वर्षों के मुनाफे के आंकड़े हजारों करोड़ रुपये के हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में आईओसी का शुद्ध लाभ करीब 39,619 करोड़, बीपीसीएल का 26,673 करोड़ और एचपीसीएल का 14,694 करोड़ रुपये का मुनाफा था। यानी तीनों कंपनियों का संयुक्त लाभ करीब 81 हजार करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में मुनाफा घटा, लेकिन कंपनियां फिर भी लाभ में रहीं। आइओसी ने 12,962 बीपीसीएल ने करीब 13,337 और एचपीसीएल ने 7,365 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। कंपनियों का लाभ जरूर काम हुआ है लेकिन घाटे जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे में 75 हजार करोड़ के मुआवजे की मांग ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या उपभोक्ताओं को नियंत्रित कीमतों पर ईंधन उपलब्ध कराने के स्थान पर पेट्रोलियम कंपनियां उपभोक्ताओं से भारी मुनाफा वसूली करना चाहती हैं।

भारत ने बदली एलपीजी रणनीति, अब अमेरिका बना सबसे बड़ा सप्लायर

खाड़ी देशों से आयात 40 फीसदी घटा, अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर 50 फीसदी पहुंची

नई दिल्ली ।

मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध ने भारत के सामने एलपीजी आपूर्ति का एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन, भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की है। कतर जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर हमले के बाद, भारत ने अपनी एलपीजी आयात रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन किया है और अब संयुक्त राज्य अमेरिका उसका सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो पहले 10 फीसदी से भी कम था।

बीते छह महीनों के आंकड़े बताते हैं कि जहां पहले भारत अपनी जरूरत का अधिकांश एलपीजी खाड़ी देशों जैसे यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत से मंगाता था, वहीं अब अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंच गई है।

मार्च में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद खाड़ी देशों से भारत का एलपीजी आयात 40 फीसदी तक कम हो गया था, जिससे देश में एलपीजी का संकट गहराने लगा था। इसी संकट के माहौल में सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अमेरिका की ओर मोड़ दिया। गौरतलब है कि युद्ध से पहले, होर्मुज जलडमरूमध्य भारत की ऊर्जा आपूर्ति का लाइफलाइन था, जिससे हमारी जरूरत का 40 फीसदी कच्चा तेल, 60 फीसदी एलएनजी और 90 फीसदी एलपीजी का आयात होता था। यह मार्ग भारत की कुल 54 फीसदी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता था। युद्ध के कारण इस मार्ग पर बढ़ते तनाव ने भारत को विकल्प तलाशने पर मजबूर किया।

अबू धाबी की एक एनर्जी एनालिस्ट के अनुसार, युद्ध शुरू होने से पहले भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर था, और इस संकट ने एशियाई देशों में उसकी धाक बढ़ा दी है। हालांकि, इस रणनीतिक बदलाव के चलते भारत को फिलहाल एलपीजी के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि अमेरिकी गैस आमतौर पर सस्ती मानी जाती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि युद्ध समाप्त होने के बाद गैस के दाम 2 डॉलर तक गिर सकते हैं। इस नए जुगाड़ से भारत की एलपीजी आपूर्ति अब मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक उथल-पुथल से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहेगी।

सरकारी बॉन्ड में एफपीआई को राहत, सेबी ने निवेशक समूह की जानकारी से छूट दी

मुंबई ।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले ऐसे निवेशकों को निवेशक समूह की विस्तृत जानकारी देने की अनिवार्यता से छूट दे दी है। इस कदम से भारत के बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पहले यह छूट केवल फुली एक्सेसिबल रूट (एफएआर) के तहत सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले एफपीआई तक सीमित थी। लेकिन अब इसे उन सभी एफपीआई तक बढ़ा दिया गया है जो सिर्फ सरकारी ऋण में निवेश करते हैं, भले ही उनका निवेश तरीका कुछ भी हो।

नियामक ने बताया कि यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उस हालिया परिपत्र के आधार पर किया गया है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों में सामान्य रास्ते से निवेश करने वाले एफपीआई के लिए एकाग्रता सीमा (कन्संट्रेशन लिमिट) का पालन करने की जरूरत को समाप्त कर दिया गया था।

चूंकि अब एकाग्रता सीमा लागू नहीं है, इसलिए सेबी ने कहा कि ऐसे एफपीआई के निवेशक समूह की पहचान करने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। इस छूट से सॉवरिन वेल्थ फंड, सेंट्रल बैंक और अन्य बड़े डेट-केंद्रित विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बॉन्ड बाजार में निवेश करना और नियमों का पालन करना आसान होगा।

सेबी ने डिपॉजिटरी और कस्टोडियन को इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जन्मदिनः 27 के हो गए शुभमन गिल

अंडर-19 विश्व कप से बनाई पहचान, कम उम्र में मिली कप्तानी, बने भारतीय क्रिकेट का सितारा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट के प्रमुख बल्लेबाजों में शुमार शुभमन गिल शानदार तकनीक, बेहतरीन टाइमिंग और धैर्य उनकी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई यादगार पारियां खेली हैं। गिल की निरंतरता और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की क्षमता ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का महत्वपूर्ण सितारा बनाया है। 8 सितंबर 1999 को फाजिल्का (पंजाब) में जन्मे गिल को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वह अक्सर अपनी उम्र से बड़े खिलाड़ियों के साथ खेला करते थे।

कैसा रहा गिल का शुरुआती सफर?

साल 2014 में उन्होंने पंजाब के अंतर-जिला अंडर-16 टूर्नामेंट में 351 रन बनाए और निर्मल सिंह के साथ 587 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी के दौरान अंडर-16 स्टेट डेब्यू में नाबाद दोहरा शतक लगाया। गिल ने साल 2017 के आखिर में रणजी ट्रॉफी में पंजाब के लिए अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू करते हुए पहले ही मैच में अर्धशतक लगाया। अगले मैच में उनके बल्ले से 129 रन निकले। शानदार प्रदर्शन की बदौलत अगले ही साल उन्हें अंडर-19 विश्व कप 2018 के लिए टीम का उपकप्तान चुना गया। अंडर-19 विश्व कप 2018 में गिल छह मुकाबलों की पांच पारियों में 124 की औसत के साथ 372 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। उन्होंने सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 94 गेंदों में सात चौकों के साथ 102 रन की नाबाद पारी खेली थी।

दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा

दाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शुभमन गिल टीम को तेज शुरुआत दिलाने के लिए मशहूर हुए। उन्हें आईपीएल 2018 के लिए नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 1.8 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। पहले ही सीजन गिल ने 13 मुकाबलों में 33.83 की औसत के साथ 203 रन बनाए। गिल को साल 2019 में वनडे डेब्यू का मौका मिला, जिसके बाद दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 45 और 35 रन बनाए। इसी सीरीज के दौरान उन्होंने सिडनी में अर्धशतक लगाने के बाद गाबा में भारत की रोमांचक जीत में 91 रन की शानदार पारी खेली थी। महज 23 साल की उम्र में गिल वनडे प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने, जिन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 149 गेंदों में 208 रन की पारी खेली।

पहले टेस्ट और फिर वनडे टीम की मिली कमान

आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने इस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गिल को फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त किया गया। इसके बाद रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद उन्हें साल 2025 के इंग्लैंड दौरे के लिए भारत का कप्तान नियुक्त किया गया। पिछले साल अक्तूबर में ही उन्हें टीम इंडिया की वनडे कमान भी सौंपी गई। शुभमन गिल भारत के लिए 43 टेस्ट मुकाबलों में 43.47 की औसत के साथ 3,043 रन बना चुके हैं। इसमें 11 शतक और नौ अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, 67 वनडे मुकाबलों में उन्होंने नौ शतक और 20 अर्धशतक के साथ 3,379 रन बना चुके हैं। वहीं, 36 टी20 मुकाबलों में उनके बल्ले से 869 रन निकले हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।

अगले साल होगी बड़ी परीक्षा

गिल के सामने 2027 में बड़ी परीक्षा है। अगले साल वनडे विश्व कप का आयोजन होना है। भारत पिछली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब अपने नाम करने से चूक गया था। भारत अगर गिल की कप्तानी में उतरता है और खिताब अपने नाम करने में सफल रहता है तो गिल तीसरे भारतीय कप्तान बन जाएंगे जिन्होंने भारत को वनडे विश्व कप का खिताब दिलाया है। अब तक सिर्फ कपिल देव (1983) और महेंद्र सिंह धोनी (2011) ही ऐसा कर चुके हैं।

पाकिस्तानी कप्तान पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय सलामी बल्लेबाज शैफाली वर्मा को महिला एशिया कप के ग्रुप मैच के दौरान आउट करने के बाद 'अपमानजनक इशारा' करने के लिए पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सोमवार को यह जानकारी दी।

यह घटना शनिवार (5 सितंबर) को भारत की पारी के दूसरे ओवर में हुई जब शैफाली वर्मा को आउट करने के बाद फातिमा ने पवेलियन की ओर इशारा किया। फातिमा को आईसीसी की खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ से जुड़ी आचार संहिता के लेवल एक के नियम 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया।

फातिमा के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जुड़ा

यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसी भाषा, हरकत या इशारे करने से संबंधित है जो बल्लेबाज का अपमान करते हों या उसे आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए उकसा सकते हों। इसके अलावा फातिमा के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक और जोड़ा गया है क्योंकि 24 महीने की अवधि में यह उनकी दूसरी गलती है।

फातिमा के दो डिमेरिट अंक हुए- इसके साथ ही एक साल के भीतर उनके डिमेरिट अंकों की संख्या बढ़कर दो हो गई है।

फातिमा को इससे पहले छह अगस्त 2025 को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच के दौरान एक डिमेरिट अंक मिला था। फातिमा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मैच रैफरी सुप्रिया रानी दास द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

क्या मिलती है सजा

मैदानी अंपायर निमाली परेरा और शथिरा जाकिर जेसी, तीसरी अंपायर रोकैया सुल्ताना और चौथे अंपायर रबाब अहसन ने उनके खिलाफ आरोप लगाया था। लेवल-एक के उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार है जबकि अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक है।

सात्विक-चिराग का आत्मविश्वास बढ़ा, अब एशियन गेम्स पर नजर

नई दिल्ली। चीन मास्टर्स जीतने के बाद, भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी एशियन गेम्स से पहले मिले 10 दिनों के समय का पूरा फायदा उठाने पर ध्यान दे रहे हैं। मौजूदा चैंपियन होने के नाते इस बड़े टूर्नामेंट में उतरने के बावजूद, इस जोड़ी का कहना है कि उन पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है। वर्ल्ड नंबर 5 भारतीय जोड़ी ने रविवार को चीन मास्टर्स के फाइनल में चीन के हे और रेन को 70 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 11-21, 21-13, 21-17 से हराया। यह जीत सात्विक और चिराग के लिए इसलिए भी खास थी, क्योंकि वे 2023 और 2025 में चीन मास्टर्स में दूसरे स्थान पर रहे थे और 2024 में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। वे 2005 में शुरू हुए इस इवेंट को जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी बन गए। चाइना मास्टर्स में यह जीत उनके करियर का 10वां बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल था और 2026 का तीसरा वर्ल्ड टूर फाइनल था। वे मई में थाईलैंड ओपन में रनर-अप रहे थे और उसी महीने के आखिर में सिंगापुर ओपन का टाइटल जीता था। चाइना मास्टर्स में उनके सफर ने उन्हें उन कुछ कमियों को दूर करने में भी मदद की जो पिछले महीने नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टरफाइनल से बाहर होने के दौरान सामने आई थीं। अपनी जीत पर बात करते हुए, इस जोड़ी ने कहा कि इस खिताब ने उन्हें एशियाई खेलों से पहले सही समय पर आत्मविश्वास दिया है। चिराग ने कहा, 'वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद हम काफी बेहतर हुए हैं। हमें समय मिला और हमने खुद को उसके हिसाब से ढाला। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे लिए मुश्किल थी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। एक मैच, और फिर हमने तुरंत

क्वार्टरफाइनल खेला। इसलिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद, हमारा शरीर एक तरह से स्थिर हो गया, उसकी आदत हो गई, और फिर हम बेहतर हुए। फिर चाइना मास्टर्स में हमें यह भी निश्चित तौर पर पता नहीं था कि पूरे हफ्ते हम शारीरिक रूप से कितना झेल पाएंगे। इसलिए हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान दे रहे थे। कुल मिलाकर, पूरे हफ्ते सब कुछ काफी सहज रहा। तो आगे के लिए यह एक अच्छा संकेत है। '

चिराग ने आगे कहा कि चीन में कई मैच खेलने के अनुभव से उन्हें अपनी शारीरिक स्थिति को लेकर और अधिक आत्मविश्वास मिला। उन्होंने कहा, 'वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमें कोर्ट पर ज्यादा समय नहीं मिला। खासकर चीन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल जैसे मुश्किल मैच से पहले। हम लगभग तीन महीनों बाद कोई टूर्नामेंट खेल रहे थे। जो पहला टूर्नामेंट हमने खेला, उसमें हमारा खेल बहुत अच्छा नहीं था। जाहिर है, मुझे लगता है कि हमारा शरीर भी उस हिसाब से ढल नहीं पाया था, जबकि यहां चाइना ओपन में हमने पांच मैच खेले, और पहले राउंड को छोड़कर बाकी सभी में हमने तीन-तीन गेम खेले। फिर भी, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले अब हमारा शरीर कहीं बेहतर महसूस कर रहा है। चाइना मास्टर्स से पहले हमें प्रैक्टिस के लिए एक हफ्ता और मिला। इससे हमें चाइना मास्टर्स में अच्छा प्रदर्शन करने में वाकई मदद मिली। '

जूनियर हॉकी एशिया कप

भारत ने दक्षिण कोरिया को 7-3 से रौंदा, सेमीफाइनल के करीब टीम इंडिया

मोकी, एजेंसी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया को 7-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के पूल ए में शीर्ष भारतीय टीम में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। मैच की बात करें तो ज्यादातर समय मुकाबला बराबरी पर रहा। शुरुआती तीन क्वार्टर में मैच काफी रोमांचक रहा, कोई भी टीम एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इंडिया ने अच्छी शुरुआत की और पांचवें मिनट में अनमोल ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके बढ़त बना ली। दक्षिण कोरिया के लिए अगले ही मिनट में डोह्योन चोई ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

दूसरे क्वार्टर में भी यही पैटर्न रहा। लवनूर सिंह ने 18वें मिनट में फील्ड गोल करके इंडिया को आगे कर दिया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने ह्योगुक यू की मदद से अगले 60 सेकंड में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। हालांकि, इंडिया ने यह पक्का किया कि वे हाफ-टाइम तक इस बढ़त को बनाए रखें। अजीत यादव ने 20वें मिनट में गोल करके इंडिया की एक गोल की बढ़त वापस ला दी और ब्रेक तक उन्हें 3-2 की बढ़त दिला दी।

दक्षिण कोरिया ने दोबारा मैच शुरू होने के बाद भी हार नहीं मानी और इंडियन डिफेंस को लगातार परखता रहा। यू एक बार फिर उनके अटैकिंग खेल का सेंटर थे, उन्होंने तीसरे क्वार्टर के सिर्फ छह मिनट में मैच का अपना दूसरा गोल किया, जिससे कोरियाई टीम तीसरी बार 3-3 से बराबर हो गई।

जब मैच आखिरी क्वार्टर में बराबरी की ओर बढ़ रहा था, तो प्रभदीप सिंह ने तीसरे क्वार्टर के आखिर में ब्रेकथ्रू पाया और 42वें मिनट में इंडिया की लीड 4-3 कर दी। चौथे क्वार्टर के शुरुआती दौर में दोनों टीमों ने एक-दूसरे पर अटैक करना जारी रखा, लेकिन इंडिया ने आखिरकार सिर्फ तीन मिनट के अंदर तीन गोल करके मैच का रुख पलट दिया।

गुरसेवक सिंह ने 55वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई। इसके एक मिनट बाद अनमोल ने पेनल्टी कॉर्नर पर फिर से गोल करके स्कोर 6-3 कर दिया। इसके बाद आर्यन जेस ने 58वें मिनट में निर्णायक गोल को 7-3 से भारत की जीत पर मुहर लगाई। कप्तान और स्टार ड्रैगफ्लिकर अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। टूर्नामेंट में उनके गोलों की संख्या आठ हो गई।

यूएस ओपन-2026

ज्वेरेव-बोटिक और गॉफ-रायबाकिना क्वार्टर फाइनल में

न्यूयॉर्क, , एजेंसी। यूएस ओपन 2026 के पुरुष एकल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव और नीदरलैंड के बोटिक वैन डे जैंडशुल्प ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ज्वेरेव ने इटली के लुसियानो डार्डेरी को सीधे सेटों में हराया, जबकि बोटिक ने दो सेट पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए आर्थर गेआ को मात दी। अब दोनों के बीच अंतिम आठ में मुकाबला होगा।ज्वेरेव ने 21वीं वरीयता प्राप्त डार्डेरी को 6-2, 6-2, 7-6(3) से हराया। जर्मन खिलाड़ी ने अपनी सर्व और दमदार बेसलाइन हिटिंग के दम पर लगातार दबाव बनाए रखा। डार्डेरी ने तीसरे सेट में अपनी पहली सर्विस और ड्रॉप शॉट के जरिए मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन ज्वेरेव ने अहम मौकों पर धैर्य बनाए रखा और तीसरा सेट टाईब्रेक में जीतकर मैच अपने नाम कर लिया।इस जीत के साथ ज्वेरेव 2026 में सभी चार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं।

दो सेट हारने के बाद बोटिक की ऐतिहासिक वापसी

दूसरी ओर, बोटिक वैन डे जैंडशुल्प ने आर्थर गेआ के खिलाफ पांच सेट के मुकाबले में शानदार वापसी की। 87वीं रैंकिंग वाले गेआ ने शुरुआती दोनों सेट 6-3, 7-6(0) से जीतकर मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना ली थी। इसके बाद बोटिक ने लगातार तीन सेट जीतकर मैच का रुख पलट दिया। बोटिक ने तीसरा सेट 7-6(7) से जीता। इस सेट के टाईब्रेक में गेआ मैच पॉइंट तक पहुंच गए थे, लेकिन अहम मौके पर उनकी फोरहैंड वॉली और एक अन्य वॉली में गलती हुई, जिसका फायदा बोटिक ने उठाया।चौथे सेट में भी गेआ मैच के लिए सर्व करने की स्थिति में पहुंचे, लेकिन वह मुकाबला खत्म नहीं कर सके। बोटिक ने टाईब्रेक 7-6(6) से जीतकर मैच को निर्णायक सेट में पहुंचाया। पांचवें सेट में उन्होंने 6-4 से जीत दर्ज की। यह मुकाबला 5 घंटे 13 मिनट चला और यूएस ओपन इतिहास का चौथा सबसे लंबा पुरुष एकल मुकाबला रहा। 30 वर्षीय बोटिक ने 2021 के बाद एक बार फिर न्यूयॉर्क में अंतिम आठ में जगह बनाई है।

कोको गॉफ ने इवा जोविक का सफर रोका, अगले दौर में पहुंची

महिला एकल में 2023 की चैंपियन कोको गॉफ ने 18 वर्षीय इवा जोविक को 6-1, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जोविक पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर तक पहुंची थीं, लेकिन गॉफ के खिलाफ उनका सफर खत्म हो गया। शुरुआत में मुकाबला कुछ हद तक बराबरी का रहा, लेकिन लय हासिल करने के बाद गॉफ ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने पहले सेट में जोविक की दो बार सर्विस तोड़ी और सेट 6-1 से जीत लिया।दूसरे सेट में जोविक ने बेहतर खेल दिखाया और गॉफ पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि, अहम मौकों पर गलतियों के कारण वह अपनी सर्विस गंवा बैठीं और गॉफ ने 6-4 से सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। जोविक ने मैच में सिर्फ नौ विनर्स लगाए, जबकि उनके नाम 30 अनफोर्स्ड एरर्स रहे। क्वार्टर फाइनल में गॉफ का सामना मिरा एंड्रीवा से होगा।

रायबाकिना ने ओसाका को हराया

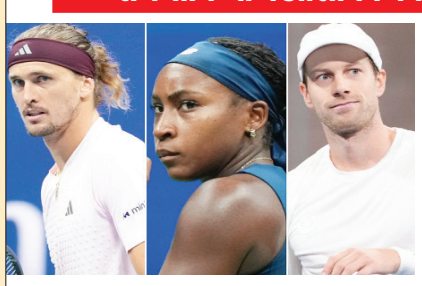

इससे पहले एलेना रायबाकिना ने पूर्व चैंपियन नाओमी ओसाका को 6-1, 6-4 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। रायबाकिना ने पहला सेट सिर्फ 22 मिनट में जीत लिया और पूरे मुकाबले में अपनी दमदार बेसलाइन हिटिंग से ओसाका पर दबाव बनाए रखा। 13वीं वरीयता प्राप्त ओसाका ने दूसरे सेट में आक्रामक शुरुआत की और अपनी सर्विस बचाती रहीं, लेकिन सातवें गेम में रायबाकिना ने अहम ब्रेक हासिल कर लिया। ओसाका को मैच के दौरान बाएं पैर में भी परेशानी हुई। इसके बावजूद उन्होंने मुकाबले में बने रहने की कोशिश की, लेकिन रायबाकिना ने 6-4 से दूसरा सेट जीतकर 66 मिनट में मैच खत्म कर दिया। इस हार के साथ 2018 और 2020 की यूएस ओपन चैंपियन ओसाका का तीसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया। रायबाकिना अब क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन झेंग किनवेन से भिड़ेंगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ये टिप्स अपनाएंगे तो हर कोई हो जाएगा आपके पर्सनैलिटी का फैन

आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या आपको लगता है अच्छे कपड़े पहनना या अंग्रेजी बोलना या फिर लोगों से मिलना पर्सनालिटी डेवलपमेंट है? तो जवाब मिलेगा नहीं। केवल यह शब्द मिलकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य नहीं करते बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। आइए कुछ टिप्स के विषय में जान लेते हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्य करते हैं।

कॉन्फिडेंस बनाएं रखें

किसी भी कार्य को आसान करने का सबसे पहला मंत्र है कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी भी काम करते समय कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। कॉन्फिडेंस से भरे लोगों से हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं को खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रयास करें। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू करें और नए-नए विषयों को एक्सप्लोर करना शुरू करें।

हर विषय पर ओपिनियन बनाने का प्रयास करें

अगर आप खुद को दूसरों से अलग बनाना चाहते हैं तो प्रयास करें कि आप हर विषय में अपना एक ओपिनियन बनाएं ताकि कभी आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें। लेकिन ध्यान रखें कि बिना मांगे ओपिनियन देने से आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव रूप में भी प्रदर्शित कर सकता है।

अच्छे श्रोता बनें

हम हमेशा उन लोगों को दूसरे के मुकाबले अधिक तवज्जो देते हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अच्छा श्रोता होना एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों को सुनना शुरू करें और एक अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करें।

बॉडी लैंग्वेज को सुधारें

पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बॉडी लैंग्वेज पर काम करना बेहद जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके बारे में कई बातें बताती है। आपके चलने, बैठने, बातें करने या खाने के तरीके सहित सब कुछ आपके आस-पास के लोगों पर प्रभाव डालता है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज एक अच्छी पर्सनालिटी की तरफ कार्य करती है।

इन तरीकों से खुद को कर सकते हैं जॉब में मोटिवेट

- खुद को शांत रखना सीखिए। ऐसा करने से आपका दिमाग ठीक तरीके से काम करता है और आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।
- ऐसे विचारों को माइंड में कभी न लाएं जो आपके किसी अच्छे काम को प्रभावित करें। हम अक्सर दूसरों से राय लेने में नहीं चूकते। जब कुछ नया करने जा रहे होते हैं। अब यह निर्भर करता है कि जिससे आपने राय ली है, वह आपका हित चाहने वाला है या नहीं, तो तुरंत किसी की बात को न मानें। उस पर विचार करें। उसके बाद ही कोई कदम उठाएं।

आज के दौर में जब जॉब की इतनी बहुतायत है, वहीं लोगों में उस जॉब को पानी के लिए जरूरी स्किल्स की कमी है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोगों में अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज तो है, पर कहीं न कहीं कई ऐसी वजहें होती है जो उन्हें अपने फील्ड में बहुत अच्छा करने से रोकती हैं। ये लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो आइए जानते हैं खुद को मोटिवेट कैसे किया जाए

- अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हों तो अपने डर पर विजय हासिल करें। कॉन्फिडेंट रहिए, डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वालों को भी अपनी ही तरह एक आम इंसान ही समझें। सोचिए कि अगर आप किसी ऊंची पोस्ट पर होते हैं तो सब आपके हाथ में होता।
- जब आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हों तो ये सोचिए कि आप कई इंटरव्यू दे चुके हैं। भले ही यह आपका पहला इंटरव्यू रहो। इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अपनी सक्सेस को हमेशा अपने साथ लेकर चलें। यह कभी न सोचें कि अगर सिलेक्शन न हुआ तो।
- जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अपनी कमियों को खुद पर हावी न होने दें। जो भी स्किल या नॉलेज आपके पास है उसे बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करें।
- साफ-सुथरी बात सभी को अच्छी लगती है। आपका बात करने का अंदाज विनम्र होना चाहिए। साथ ही स्पष्ट और कम शब्दों में होना चाहिए।

बहुत बड़ा है एविएशन इंडस्ट्री का दायरा

अगर आप भी एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को पायलट व केबिन क्रू बनने के काबिल नहीं पाते, तो निराश मत हो, क्योंकि इसके अलावा भी अब इस सेक्टर में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। ज्यादातर लोग एविएशन क्षेत्र के दायरे को पायलट, एयर होस्टेज व केबिन क्रू तक सीमित कर देते हैं, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। आप इस इंडस्ट्री में एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, फ्लाइट इंजीनियर, एयर टिकटिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, एयर कार्गो मैनेजमेंट, मीटिरियोलॉजिस्ट आदि जॉब प्रोफाइल पर भी कार्य कर सकते हैं।

ग्राउंड स्टाफ

एविएशन इंडस्ट्री में ग्राउंड स्टाफ महत्वपूर्ण होते हैं। इनका कार्य एयरपोर्ट की साफ-सफाई के साथ उसके रखरखाव करना है। एयरपोर्ट पर प्लेन जब उतर जाता है, तो उसके बाद पैसेंजरों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर सामान ढुलाई और माल स्टॉक का कार्य भी ग्राउंड स्टाफ को ही कराना होता है। ग्राउंड स्टाफ की एयरपोर्ट पर अलग-अलग कार्य की जिम्मेदारी संभालते हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में करियर बनाने के लिए आप एयरपोर्ट मैनेजमेंट से रीलेटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर लेवल के कोर्स कर इस फील्ड में प्रवेश कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप इस सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं।

एयर कार्गो मैनेजमेंट

इस जॉब प्रोफाइल पर रहकर करियर बनाने के लिए आपको डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयर कार्गो मैनेजमेंट कोर्स करना होगा। जिसमें आप एविएशन हिस्ट्री एवं जियोग्राफी के अतिरिक्त कार्गो लॉ, कस्टम्स रूल्स, वेयरहाउसिंग, एयरक्राफ्ट लिमिटेशन व लोडिंग कैपेसिटी, क्लीयरेंस प्रोसिजर, क्लेम रूल्स, बीमा और फ्री ट्रेड जोन जैसे विषयों से रूबरू होंगे। इस क्षेत्र में भी प्रवेश के लिए आपको न्यूनतम 12वीं की शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। यह कोर्स आपको 6 माह से 1 वर्ष तक का होता है।

एयर टिकटिंग

एविएशन के एयर टिकटिंग में करियर बनाने के लिए न्यूनतम 12वीं की शैक्षणिक योग्यता के साथ 18 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए। न्यूनतम 6 माह से 9 माह तक की अवधि वाले कोर्स डिप्लोमा इन एयर टिकटिंग एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में ट्रैवल एजेंसी बिजेनस, वर्ल्ड टाइम जोन, एयरपोर्ट व एयरलाइन कोड्स, पेमेंट मोड्स, फॉरेन करेंसी, पासपोर्ट व वीजा आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

फ्लाइट इंजीनियर

एविएशन के क्षेत्र में फ्लाइट इंजीनियर का कार्य बहुत अहम होता है। प्लेन के सभी पुर्जों की जांच करना इनकी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, एयरोनॉटिकल या कम्प्यूटर में से किसी एक में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आपके पास फ्लाइट इंजीनियर का ग्राउंड पाठ्यक्रम या एयर क्राफ्ट इंजीनियर लाइसेंस या सीपीएल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने 12वीं विज्ञान विषयों से पास की हो और आपकी उम्र तीस साल से ज्यादा ना हो, तो आप इसमें करियर बना सकते हैं।

एयर ट्रैफिक कंटोलर्स

एविएशन के क्षेत्र में यह एक और महत्वपूर्ण जॉब प्रोफाइल है। एयरपोर्ट पर बने टॉवर से एयर ट्रैफिक कंटोलर्स हर वक्त प्लेन की उड़ानों पर नजर रखते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के आपको रेडियो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग बीटेक या डिप्लोमा करना होगा।

मीटिरियोलॉजिस्ट

एविएशन में मीटिरियोलॉजिस्ट का भी बड़ा रोल होता है। इसमे कैरियर बनाने के लिए अगर आपके पास मौसम विज्ञान, भौतिक, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गणित और दूरसंचार में ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई करने योग्य हैं।

टूर एंड ट्रैवल

अगर आप एविशन के क्षेत्र में रहकर अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं तो टूर एंड ट्रैवल आपके लिए बेस्ट होगा, इस क्षेत्र में आपको बहुत काम मिलेगा। इस क्षेत्र में आने के लिए आप 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर तीन वर्षीय बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं।

यहां से कर सकते हैं कोर्स

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, नई दिल्ली
- फ्रांकलिन एविएशन एकेडमी, दिल्ली
- विंग्स कॉलेज ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी, पुणे
- ए जे एविएशन एकेडमी, मुम्बई
- राजीव गांधी एविएशन एकेडमी, हैदराबाद
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स साइंस, जमशेदपुर
- हिंदुस्तान एविएशन एकेडमी, बंगलूरू

क्या है आर्कियोलॉजी? किस कोर्स के बाद मिलेगी हाई सैलरी

अगर आप इतिहास से लगाव रखते हैं और आप रोमांच के साथ रहस्य से पर्द उठाना चाहते हैं। साथ ही आपमें ऐतिहासिक चीजों को जानने और उनके बारे में तरह-तरह की जानकारियां पता करने की इच्छा है तो आप आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। इतिहास और भूगोल के रहस्यों से पटे भारत में इसके अच्छे

हड़प्पा सभ्यता के बाद से भारत में ऐतिहासिक खोज न के बराबर हुई है और फिलहाल इतिहास संबंधित खोज को लेकर एक बड़ा वैक्यूम यहां बना हुआ है, जो बड़े आइडियाज और क्रिएटिविटी का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही दुनियाभर में शोध के लिए आर्कियोलॉजी के विद्यार्थियों की मांग है।

क्या है आर्कियोलॉजी

पृथ्वी पर छपी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना व उनकी खोज करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजी में उस इतिहास के बारे में यह जानने की कोशिश की जाती है कि पुरानी सभ्यताओं में लोगों का रहन- सहन कैसा था। किस तरह की वस्तुओं का वो इस्तेमाल करते थे। अनुमानों

लेकर तत्कालीन समाज और परिवेश के आकलन का काम भी एक आर्कियोलॉजिस्ट को करना होता है। साथ ही वह कार्बन डेटिंग और समय गणना का काम भी करता है। सभी तरह के ऐतिहासिक वस्तु या सभ्यता के वर्तमान से जुड़ाव और विकास के क्रम को निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी एक आर्कियोलॉजिस्ट की होती है।

किस तरह का होता है कोर्स

अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको 12वीं की परीक्षा इतिहास विषय के साथ पास करनी होगी। इसके बाद आप

आर्कियोलॉजी में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर और पीएचडी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें प्रवेश के लिए अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इससे जुड़े कोर्स देश के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों से किए जा सकते हैं। मास्टर इन कंजर्वेशनए प्रिजरवेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट और मास्टर इन आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट जैसे कोर्स इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की सीढ़ी हो सकते हैं। इसके अलावा आप हिस्टॉरिकल आर्कियोलॉजी, जिओ आर्कियोलॉजी, आर्कियोबॉटनी, क्रॉनोलॉजिकल, एथनोआर्कियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल ऑर्कियोलॉजी, आर्कियोमेट्री जैसे कोर्स भी कर सकते हैं।

जरूरी योग्यता

एक बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट अथवा म्यूजियम प्रोफेशनल बनने के लिए प्लीस्टोसीन पीरियड अथवा क्लासिकल लैंग्वेजए मसलन पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, अरेबियन भाषाओं में से किसी की जानकारी आपको कामयाबी की राह पर आगे ले जा सकती है। आर्कियोलॉजी न केवल दिलचस्प विषय है बल्कि इसमें कार्य करने वाले प्रोफशनल्स के लिए चुनौतियों में भरा क्षेत्र भी है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमताए तार्किक सोचए कार्य के प्रति समर्पण जैसे महत्वपूर्ण गुण जरूर होने चाहिए। कला की समझ और उसकी पहचान भी आपको औरों से बेहतर बनाने में मदद करेगा।

यहां से कर सकते है कोर्स

- आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
- बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
- दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट
- कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी

जॉब ऑप्शन क्या हैं

आर्कियोलॉजी में कोर्स पूरा करने के बाद आपको जॉब के कई ऑप्शन मिलेंगे। जिनमें मुख्य रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली, राज्यों में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, विभिन्न संग्रहालय, एनजीओ और यूनिवर्सिटी, विदेश मंत्रालय का हिस्टोरिकल विभाग, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन विभाग, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आदि।

सैलरी व संभावनाएं

यह ऐक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको रोमांच और रहस्य के साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप 30 से 50 हजार रूपये प्रतिमाह की जॉब आसानी से पा सकते हैं, जो अनुभव व आपकी खोज के साथ

जॉब प्रोफाइल के हिसाब से लाखों रूपये की सैलरी पा सकते हैं।

इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करियर बनाना है बेहद आसान

इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पिछले कुछ सालों से लगातार तेजी से विस्तार कर रही है, जिसके चलते एक्चुरियल प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी बढ़ गया है। अगर आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो यह समय काफी अच्छा है, खास कर कोरोना के बाद इंश्योरेंस के हेल्थ सेक्टर में बूस्ट आया है। आज के समय लगभग हर परिस्थिति से निपटने के लिए बीमा कंपनियों के पास पॉलिसी हैं। जीवन बीमा, यात्रा बीमा, वाहन बीमा, स्वस्थ्य बीमा तथा गृह बीमा इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित हैं।

एजुकेशन

इस क्षेत्र में जाने के लिए आप 12वीं व ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन विषय का पूरा ज्ञान लेने के लिए एक्चुरियल साइंस से संबंधित कोर्सेस में स्नातक डिग्री के लिए मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स में 55 प्रतिशत अंकों के साथ बारहवीं पास होना आवश्यक है जबकि पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मैथ्स-स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स सब्जेक्ट से स्नातक जरूरी है। स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुरी प्रोफेशनल बनने के लिए स्टूडेंट्स को एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया का फेलो मेंबर होना जरूरी है। यह संस्थान इसमें कोर्सेस भी कराता है।

इंश्योरेंस का कार्य क्षेत्र

इसके लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस और फाइनेंस इंडस्ट्री में जोखिम का अनुमान लगाते हैं। एक्चुरियल प्रोफेशनल्स यह हिसाब लगाते हैं कि किसी पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम के तौर पर कितनी राशि का भुगतान करना होगा या किसी कंपनी को पेंशन या रिटर्न पर कितना खर्च करना होगा। प्रोफेशनल का काम अचानक घटी घटना के आर्थिक प्रभाव का अंदाजा लगाने का भी होता है। आज इस क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स को इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बैकबोन भी कहा जाने लगा है।

स्किल व एलिजिबिलिटी

इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए खुद को अपडेट रखना जरूरी है। खुद में लोगों की परेशानी को समझने, नई तकनीक सीखने में हिचकिचाहट न होने, कम्युनिकेशन के साथ मैथ और स्टेटिस्टिक्स पर पकड़ मजबूत रखने जैसे स्किल का होना जरूरी है। अपनी योग्यता के आधार पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड असिस्टेंटए डेवलपमेंट ऑफिसरए इंश्योरेंस एजेंटए इंश्योरेंस सर्वेयरए एक्चुरी मैनेजरए रिस्क मैनेजर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं।

जॉब्स के अवसर

अगर आपके पास एक्चुरियल साइंस की डिग्री है तो आपके लिए इन दिनों नौकरियों के लिए कई रास्ते खुल गए हैं। इंश्योरेंस, बैंकिंग, बीपीओ-केपीओ, आईटी सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनियों, फाइनेंशियल कंपनियों आदि में इनके लिए अच्छे मौके होते हैं। दूसरी तरफ, बीपीओ कंपनी में भी जोखिम के बारे में विश्लेषण करने के लिए बड़े पैमाने पर एक्चुरियल प्रोफेशनल्स की हायरिंग होती है। बीपीओ में काम करने वाले एक्चुरी प्रोफेशनल्स की सैलरी भी आम बीपीओ एंप्लॉइज की तुलना में दो से तीन गुना अधिक होती है।

भारत में संभावनाएं इसलिए भी अधिक हैं, क्योंकि वैश्विक ग्राहकों को कम संसाधन और न्यूनतम लागत में अच्छी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। वहीं एक्चुरियल प्रोफेशनल्स की डिमांड सरकारी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में ही नहीं, बल्कि टेरिफ एडवाइजरी कमिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, फाइनेंशियल एनालिसिस फर्म में भी है।

सैलेरी

इस क्षेत्र में आप फ्रेशर के तौर पर प्रतिमाह 20 से 30 हजार रुपये तक आसानी से पा सकते हैं। वहीं अनुभव व समय के साथ किसी उच्च पद पर पहुंचने पर आप 1 लाख रुपये का मासिक वेतनमान भी ले सकते हैं। यदि आपने किसी टॉप कॉलेज से एमबीए इन इंश्योरेंस किया है तो आप अपनी फर्स्ट जॉब में ही ज्यादा बेहतर वेतनमान की अपेक्षा कर सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

कालेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय
एकेडमी ऑफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट, दिल्ली
बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, दिल्ल
इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई
एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे
एमिटी स्कूल ऑफ इंश्योरेंस एंड एक्चुरियल साइंस, नोएडा

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सारण में बाढ़ के कारण 95 स्कूल बंद, बच्चों की पढ़ाई पर लगा ब्रेक

छपरा (एजेंसी)। बिहार के सारण जिले में नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ का कहर अब बच्चों की शिक्षा पर भारी पड़ने लगा है। सोनपुर से लेकर छपरा सदर तक फैले बाढ़ के पानी ने जिले के 95 विद्यालयों में पठन-पाठन को पूरी तरह ठप किया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सभी विद्यालयों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित सोनपुर प्रखंड है, जहां 47 विद्यालयों को बंद किया है। इसके अलावा, दिघवारा में 17, छपरा सदर में 20, गड़खा में 6 और रिविलगंज में 5 विद्यालय बाढ़ के कारण बंद हैं। कई स्कूलों के परिसरों में पानी घुस गया है, वहीं कुछ स्थानों पर विद्यालय तक पहुंचने वाले रास्ते भी पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन उन इलाकों पर भी पैनी नजर रख रहा है जहां पानी तेजी से बढ़ रहा है और जरूरत पड़ने पर अन्य विद्यालयों को भी बंद किया जा सकता है। हालांकि, शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की हैं। बंद किए गए विद्यालयों के शिक्षकों को आसपास के अन्य विद्यालयों में संलग्न (अटैच) किया गया है, ताकि उनकी सेवाओं का उपयोग जारी रहे और नजदीकी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहे। साथ ही, प्रभावित विद्यालयों के बच्चों को यह सुविधा दी गई है कि वे अपनी इच्छा अनुसार समीप के किसी भी खुले विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जैसे ही इन विद्यालयों से पानी निकलेगा, 24 घंटे के भीतर उन्हें फिर से खोलने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। प्रशासन बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

9वीं के छात्र के साथ रैगिंग, 5 गिरफ्तार

सोलन (एजेंसी)। सोलन के मशहूर डीपीएस डगशाई में नौवीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट और रैगिंग का मामला सामने आया है। इसी स्कूल के 5 सीनियर छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक बीते 5 सितंबर को नौवीं कक्षा के एक मासूम छात्र को सीनियर छात्रों ने उसके हॉस्टल के कमरे से जबरन घसीटकर बाहर निकाला और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। जूनियर छात्रों का आरोप है कि पिछले चार महीनों से सीनियर छात्र उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। रैगिंग, गाली-गलौज और शारीरिक हमला यहां आम बात हो चुकी थी। इसी खौफ की वजह से जूनियर छात्र पिछले कई महीनों से भयंकर मानसिक तनाव और डर के साये में जी रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने लंबे जाम में फंसे लोगों को दी राहत खुद खुलवा दिए सारे टोल गेट

त्रिशूर (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने केरलम के त्रिशूर में एनएच-544 पर पलियक्कारा टोल प्लाजा के सभी 12 गेट खोलने का आदेश दिया। ऐसा उन्होंने टोल प्लाजा के दोनों तरफ 2 किलोमीटर से अधिक लंबा ट्रैफिक जाम लगने के कारण किया। केंद्रीय मंत्री शाम करीब 5.45 बजे त्रिशूर से एर्नाकुलम जा रहे थे जब उनका काफिला मन्नुथी-अंगमाली स्ट्रेच पर पहुंचा और उन्हें इस भारी जाम का सामना करना पड़ा। भारी जाम के बीच, केंद्रीय मंत्री के पुलिस एस्कॉर्ट ने उनके लिए रास्ता बनाया। हालांकि, इतनी लंबी कतार देखकर मंत्री गोपी ने अपनी जिम्मेदारी समझी और तत्काल हस्तक्षेप का फैसला किया। उन्होंने बताया कि कानूनी नियमों के अनुसार, यदि वाहन लंबी लाइनों में फंसे हों, तब इंजन चालू रहने से ईंधन की बर्बादी और धुएं के उत्सर्जन को रोकने के लिए अदालत के निर्देश हैं कि टोल गेट खोल दिए जाएं ताकि वाहनों को आगे बढ़ने दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री गोपी ने स्पष्ट किया कि टोल स्टाफ केवल अपना काम कर रहे थे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाम के लिए जिम्मेदार नहीं मन सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को भारी ट्रैफिक वाले दिनों में पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए और टोल प्लाजा पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। त्रिशूर के सांसद ने स्वीकार किया कि उनके काफिले के निकलने पर कुछ वाहन चालकों को गुस्सा आया होगा, लेकिन उन्हें इस बात से संतुष्टि मिली कि बाद में सभी यात्री आगे बढ़कर राहत महसूस कर पाए।

पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल से नकली पीएमओ अधिकारी गिरफ्तार बंदूक भी बरामद

मुंबई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई में होने वाले कार्यक्रम स्थल, नीता अंबानी कल्चरल सेंटर, से पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से एक व्यक्ति के पास से एक लोडेड बंदूक बरामद हुई है। गिरफ्तार मुख्य संदिग्ध खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का अधिकारी बता रहा था। मुंबई पुलिस ने 24 वर्षीय रोहन पारेख नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पीएमओ का एक नकली पहचान पत्र मिला। सुरक्षा अधिकारियों को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ, जिसके बाद जांच करने पर पहचान पत्र फर्जी निकला। रोहन एक निजी बॉडीगार्ड के साथ घूम रहा था, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से भरी हुई पिस्तौल बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।

सवाल पूछने पर दिमागी नक्सल और नाराज़ फूफा जैसे अपमानजनक लेबल लगते हैं

-पीएम मोदी की दिमागी नक्सलियों वाले भाषण पर राहुल गांधी ने बोला तीखा हमला

नई दिल्ली, एजेंसी।
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए दिमागी नक्सलियों वाले भाषण के कीरब तीन हफ्ते बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को उन पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं और जवाबदेही से बचने के लिए ऐसे विवादास्पद शब्दों का सहारा लेती है। उन्होंने विशेष रूप से दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे का हवाला दिया, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की जान चली गई।

राहुल गांधी ने एक्स पर ये बातें कहीं। उन्होंने टिना हैशटैग का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है उन्होंने कोई जवाबदेही नहीं बताया। गौरतलब है कि पीएम मोदी के समर्थक टिना फ़ैक्टर का ज़िक्र करते हैं, जिसका मतलब वे कोई विकल्प नहीं बताते हैं। यह पहली बार है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले तंज का जवाब दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार से सवाल पूछने वाले किसी भी व्यक्ति को दिमागी नक्सल कह देती है। सोमवार को हिंदी में किए गए अपने एक्स पोस्ट में राहुल ने कहा कि बीजेपी हमेशा निचले स्तर के अधिकारियों को दोषी ठहराती है और असली दोषियों को बच निकलने देती है, साथ ही, वह त्रासदी को रोकने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाती। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की सत्य निकेतन त्रासदी कोई अकेली घटना नहीं है और पिछले चार महीनों में राजधानी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले चार महीनों में सैदुलजाब में इसी तरह की त्रासदी में छह लोगों की मौत हुई और हौज़ रानी में आग लगने से 22 लोगों की जान चली गई थी। हर बार, लोगों की जान, सपने और उम्मीदें मलबे के नीचे दब जाती हैं और हर बार, कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। उन्होंने आगे कहा कि और जब आप जवाबदेही की मांग करते हैं, तो पीएम खुद आप पर दिमागी नक्सल और नाराज़ फूफा जैसे अपमानजनक लेबल लगाते हैं- मकसद यह होता है कि सवाल पूछने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा किया जाए, बदनाम किया जाए और चुप करा दिया जाए। राहुल ने कहा कि दिल्ली में ट्रिपल-इंजन सरकार है, इसलिए इस घटना की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए उसके पास कोई बहाना नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह बेबसी इच्छाशक्ति की कमी से पैदा होती है क्योंकि जहां इच्छाशक्ति नहीं होती, वहां जवाबदेही भी नहीं होता।

राफेल मानहानि केस में राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका

मुंबई (एजेंसी)। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को गिरगांव मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए छह सप्ताह की राहत दी है। न्यायमूर्ति नितिन बोरकर ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में ऐसी कोई स्पष्ट अवैधता या गंभीर खामी नहीं है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर हस्तक्षेप करना चाहिए। यह मानहानि शिकायत भाजपा सदस्य महेश श्रीश्रीमल ने गिरगांव मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की थी। शिकायत के अनुसार, राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से भाजपा समर्थकों की भावनाएं आहत हुई थीं। मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2019 में राहुल गांधी को समन जारी किया था। उन्हें जुलाई 2021 में समन मिला, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप पसबोला ने शिकायत को राजनीति से प्रेरित और परेशान करने के उद्देश्य से दायर बताया। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता को मानहानि मामले में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहन महाडिक और महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने याचिका का विरोध किया।

पुलिस छात्रों को परेशान करने और महिला पत्रकारों के साथ मारपीट करने में व्यस्त

-अभिजीत दीपके ने पोस्ट में लिखा- दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी

नई दिल्ली, एजेंसी।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस छात्रों को परेशान करने में बिजी हैं। दीपके ने सोशल मीडिया पर एक न्यूजपेपर की कटिंग शेयर की है, जिसमें लिखा है-दिल्ली के किलोकरी गांव में 54 साल के मणिपुरी म्यूजिशियन सी विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। विक्रम अपने अपार्टमेंट के बाहर शराब पीने और शोर मचाने वाले लोगों का विरोध कर रहे थे। उनके घर के बाहर एक ग्रुप ने उन पर हमला किया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका बेटा उन्हें अस्पताल ले गया जहां उनकी मौत हो गई।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत ने ये न्यूजपेपर की कटिंग शेयर करते हुए लिखा- दिल्ली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। दिल्ली पुलिस छात्रों को परेशान करने और शाहीन व नफीसा जैसी महिला पत्रकारों के साथ मारपीट करने में तो बहुत व्यस्त है, लेकिन असल अपराध को रोकने के लिए उसके पास समय नहीं है। एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाली दो महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पहचान की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया।
3 सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के साकेत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए गई थीं। पत्रकारों का आरोप है कि वह कार्यक्रम की वीडियो बना रही थीं। तभी पुलिस वालों ने उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि एक सीएम से सवाल पूछने की सजा है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी फस्टेशन निकाल दिया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने चोट के निशान दिखाए हैं। उन्होंने बताया कि ये निशान दिल्ली पुलिस के डंडे से चोट के हैं।

अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान को चुनाव में खेला करना चाहती है बीजेपी

-संगीत सोम ने कहा- जिसे वह चवन्नी समझ रहे हैं वह उन्हें एकन्नी का भी नहीं छोड़ेंगे

लखनऊ, एजेंसी।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में जाट नेता और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को चवन्नी बताया था। अब पूरी कोशिश हो रही है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए। आरएलडी चीफ चौधरी ने कहा कि जाट समुदाय का इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने जयंत चौधरी का पक्ष लेते हुए कहा था कि अखिलेश यादव जिसे चवन्नी समझ रहे हैं वह उन्हें एकन्नी का भी नहीं छोड़ेंगे।
वहीं जयंत ने कहा कि अगर सियासत की प्रतिद्वंद्विता में कुछ कहना ही था तो मेरा नाम लेकर कहा जा सकता था। एक समुदाय का इस तरह का अपमान करना उन्हें पतन के रास्ते पर ले जाएगा। उन्होंने कहा, इस तरह का अहंकार पहले भी देख चुका हूं। यह केवल पतन का रास्ता है। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर ने भी कहा कि जाट समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा कि इसी जाट समुदाय ने अखिलेश यादव के पिता को सीएम बनाया था। उन्होंने यहां तक कहा कि अखिलेश यादव का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। जयंत चौधरी विपक्ष पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में सहारनपुर की रैली में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गन्ने के मुद्दे का भी राजनीतीकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन से किसान एक और बाजार से जुड़ रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी से देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा 400 पार तो गन्ने का दाम 400 पार वाला नारा भी दिया। जयंत चौधरी को बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड माना जा रहा है।

आरएलडी लंबे समय से जाट और किसानों की राजनीति करती रही है। कभी जाट और मुस्लिमों पर पार्टी का फोकस हुआ करता था। वहीं अब जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन होने के चलते ब्राह्मण समाज को भी फोकस में रखना शुरू कर दिया। 2027 के चुनाव में जयंत चौधरी इसी समीकरण का फायदा उठाना चाहते हैं। एनडीए में रहते हुए अगर वह सवर्ण वोटों में सेंध लगाते हैं तो यह एनडीए के लिए फायदेमंद होगा। जयंत 2027 के चुनाव में 33 से 38 सीटों पर हिस्सेदारी चाहते हैं। इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके साथ ही उनकी पत्नी चारू चौधरी भी सक्रिय राजनीति में हैं। ऐसे में महिला वोटों में भी उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है। वहीं बीजेपी आरएलडी को 20 से 25 सीटें देना चाहती है। अगर जयंत चौधरी अखिलेश यादव के खिलाफ इसी तरह मजबूत रहते हैं तो आरएलडी को ज्यादा सीटें भी दी जा सकती हैं।

दिल्ली बिल्डिंग हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश : अब पूरे देश में होगी असुरक्षित इमारतों की जांच

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना के मद्देनजर पूरे देश में इमारतों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच करने पर विचार कर रहा है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर.महादेवन की बेंच ने मामले पर यह भी कहा कि वह सत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे मन में पहले से यह योजना है कि पूरे देश में ऐसी जांच होनी चाहिए। हम इसे (दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही याचिका को) यहां ट्रांसफर करवा सकते हैं। हम इस मामले पर परसों यानी 10 सितंबर को सुनवाई करेंगे। कोर्ट का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) और सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर एक याचिका का जिक्र किया। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें देश भर के प्राइवेट पीजी अकोमोडेशन, हॉस्टल और छात्रों के रहने की अन्य सुविधाओं के निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की गई थी। अजीत कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि हाल ही में हुई दुखद घटना को देखते हुए, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है।

टास्मैक घोटाले और करूर गैंग का मुद्दे पर सीएम विजय ने विपक्ष को घेरा

चेन्नई, एजेंसी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में राज्य की सरकारी शराब कंपनी टास्मैक में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकार पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए कि 2021 से 2025 के दौरान राज्य में एक संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसे करूर गैंग के नाम से जाना जाता था। यह हमला राज्य के राजनीतिक गलियारों में गरमाहट पैदा कर गया है, खासकर तब जब सत्ताधारी दल नई-नई सत्ता में आया है।

मुख्यमंत्री विजय ने आरोप लगाया कि इस गिरोह ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बड़े पैमाने पर अवैध वसूली, टेंडरों में हेराफेरी और पैसों का अवैध लेनदेन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उस समय यह विभाग पिछली सरकार के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के पास था, जिससे सीधे तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। विजय ने आरोप लगाया कि सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर निजी लोगों और राजनीतिक बिचौलियों को अनुचित रूप से ताकत दी गई थी, जिससे एक समानांतर व्यवस्था का निर्माण हुआ जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी। उन्होंने सदन को बताया कि करूर और कोयंबटूर जैसे इलाकों में शराब खरीदने वालों से तय कीमत से अधिक पैसे वसूले जाते थे और स्थानीय बार मालिकों से जबरन उगाही की जाती थी, जिससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हुआ और जनता का शोषण हुआ। मुख्यमंत्री ने सेंथिल बालाजी के भाई वी. अशोक कुमार का नाम लेते हुए उन पर फर्जीवाड़े, टेंडर में गड़बड़ी और ट्रांसपोर्ट व खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट से अवैध पैसे ट्रांसफर करने का सीधा आरोप लगाया, जिससे घोटाले की जड़ें और गहरी होती दिख रही हैं। अपने भाषण में, विजय ने 1967 में सी.एन. अन्नादुरई, 1977 में एम.जी. रामचंद्रन और 1983 में एन.टी. रामा राव (आंध्र प्रदेश) की ऐतिहासिक राजनीतिक जीतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर, उनकी दो साल पुरानी पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके) ने 2026 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करके सरकार बनाई है, जो राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक नया मील का पत्थर है और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने दृढ़ता से कहा, ईश्वर, प्रकृति और जनता हमेशा हमारे साथ हैं। भ्रष्टाचार विरोधी जांच के सामने विपक्ष के सारे दांव उल्टे पड़ेंगे। यह बयान उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है और यह भी इंगित करता है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी। सी. जोसेफ विजय विधानसभा में गृह (पुलिस) विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे, जो विभाग स्वयं उनके पास है।

नंदीग्राम : जहां ममता खुद हार गईं, वहां किसे लड़ाएगी टीएमसी

कोलकाता, एजेंसी।
पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जहां 6 अक्टूबर को मतदान होगा और 9 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि, इस बार की चर्चा उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर है, जो अभी तक सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी दोनों की ओर से नहीं की गई है। यह वही महत्वपूर्ण सीट है जहां 2021 के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हराया था, जिससे यह उपचुनाव और भी दिलचस्प हो गया है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा यह सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव हो रहा है। टीएमसी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें अखिल गिरि का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि, पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। टीएमसी इस सीट पर अपनी वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, क्योंकि यह ममता बनर्जी की चुनावी हार का प्रतीक रही है। वहीं, भाजपा ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक, मेघनाद पाल के नाम की चर्चा है, जिन्हें सीएम अधिकारी का करीबी माना जाता है। भाजपा का दावा है कि पार्टी की ओर से जिसे भी नामित किया जाएगा, वह उम्मीदवार मतदाताओं के लिए स्वीकार्य होगा। दोनों ही प्रमुख दल रणनीति के तहत नामों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, जिससे यह मुकाबला और भी कड़ा होने की उम्मीद है। नंदीग्राम के साथ ही पश्चिम बंगाल की एक और सीट रेजीनगर में भी उपचुनाव होना है। यह सीट आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) प्रमुख हुमायूं कबीर के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी। कबीर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता थे, जिन्होंने पार्टी से निकाले जाने के बाद एजेयूपी का गठन किया और 2021 के विधानसभा चुनाव में रेजीनगर सीट पर जीत हासिल की थी। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट और असम के नगांव लोकसभा क्षेत्र में भी 6 अक्टूबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की है।

गणेशोत्सव: मुंबई में ध्वनि और अन्य नियमों का कड़ा पालन होगा

मुंबई , एजेंसी।
मुंबई में गणेशोत्सव का उल्लास इस वर्ष कड़े ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों और अन्य व्यवस्थाओं के साथ मनेगा। बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति ने शहर के सभी गणेश मंडलों से अपील की है कि वे लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि उपकरणों का इस्तेमाल निर्धारित सीमाओं के भीतर ही करें। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत, आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि स्तर 55 डेसिबल और रात 10 बजे के बाद 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। समन्वय समिति ने मंडलों से डीजे के बजाय ढोल-ताशे और पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ उत्सव मनाने का आग्रह किया है। गणपति विसर्जन के चार प्रमुख दिनों 15, 18, 19 और 25 सितंबर को लाउडस्पीकर रात 12 बजे तक चलाने की अनुमति होगी। हालांकि, इस दौरान भी ध्वनि की निर्धारित सीमा का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि देर रात तक अनुमति का अर्थ तेज आवाज में संगीत बजाने की छूट नहीं है, और नियम तोड़ने पर संबंधित मंडल या आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
महाप्रसाद की गुणवत्ता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब महाप्रसाद तैयार करने वाले सप्लायर के पास खाद्य सुरक्षा से जुड़ा वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। इस नियम से छोटे गणेश मंडलों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनके सीमित बजट में लाइसेंसधारी सप्लायर की सेवा लेना कठिन है। उन्होंने एफडीए से छोटे मंडलों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की है।
गणेश मूर्तियों की ऊंचाई और विसर्जन को लेकर भी मंडलों में असमंजस बना हुआ है। समन्वय समिति ने महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और संबंधित विभागों से अदालत के निर्देशों के अनुसार एक स्पष्ट और साझा नीति बनाने की मांग की है। बॉम्बे हाई कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था के तहत, छह फीट तक की प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में और छह फीट से ऊंची मूर्तियों को प्राकृतिक जलस्रोतों में विसर्जित करने की अनुमति है। समिति का कहना है कि नीति लागू करते समय मुंबई की सड़कों, विसर्जन मार्गों, पुलों और अन्य बाधाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

फ्रांस में पहला हिंदू मंदिर: प्राण प्रतिष्ठा में 40 देशों से पहुंचे मेहमान

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रविवार को देश का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बीएपीएस अक्षरधाम संस्थान के गुरु महंतस्वामी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरा किया। इसमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से आए संतों, भक्तों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय वास्तुकला और वैदिक शिल्पशास्त्र के आधार पर किया गया है। इसमें फ्रांसीसी आधुनिक तकनीक का भी सुंदर मेल देखने को मिलता है। 13 दिनों तक चले इस महोत्सव में 40 से अधिक देशों से लोग शामिल हुए। प्रतिष्ठा से पहले पेरिस में एक भव्य नगर यात्रा निकाली गई। यात्रा में 14 सुसज्जित रथों पर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां सजाई गईं। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुतियां दीं। यात्रा एफिल टावर और एकोल मिलिटेर से होते हुए प्लास द ला कॉनकॉर्ड तक पहुंची। यात्रा ने फ्रांस में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का नया अध्याय खोल दिया। यह मंदिर 5000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है। ऊपरी तल पर पारंपरिक मंदिर और नीचे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हवेली बनाई गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रभुपाद ने भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक वैभव के पुनर्जागरण का अभियान शुरू किया था। आज उसका प्रकाश यूरोप समेत पूरी दुनिया में फैल रहा है। 2024 में अबू धाबी में भी एक भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ था। यह निर्माण संतों की संकल्प शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा, बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था और करोड़ों हरि भक्तों को इस अवसर पर बधाई दी गई। बीएपीएस मंदिरों से भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य प्रसारित होते हैं। यह मंदिर फ्रांस की विविधता को समृद्ध करेगा और सांस्कृतिक संबंधों को ऊर्जा देगा। भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। दोनों देश राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं। उन्होंने कहा, यह साझेदारी पुराने सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत बुनियाद पर टिकी है। फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदान का इतिहास आज भी जीवित है। फ्रेंच स्कॉलर्स ने संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद पर रोमा रोला की लेखनी समाजों को करीब लाई। प्रधानमंत्री ने कहा, दशकों पहले श्रील प्रभुपाद स्वामी ने फ्रांस आकर आध्यात्मिक संबंधों का नया अध्याय शुरू किया था। आज योग भी भारत और फ्रांस के लोगों के बीच जुड़ाव का एक अहम जरिया बन चुका है। यह स्वामी नारायण मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके पत्थर भारत में तराशे गए हैं। भारत की प्राचीन प्रतिभा फ्रांस की आधुनिक इंजीनियरिंग से जुड़कर इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है। यह मंदिर सदियों तक दोनों देशों के बीच सहयोग और संभावनाओं का प्रतीक बनेगा और सेवा प्रकल्पों का केंद्र होगा।

गाजा को लेकर इस्राइल से नाराज है यूएस?: अमेरिकी प्रतिनिधि कुशनर का बड़ा बयान- बेतुकी कार्रवाई कर रहे नेतन्याहू

कीव, एजेंसी। अमेरिकी विशेष दूत और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने रविवार को कहा कि इस्राइल में होने वाले नेसेट चुनाव की वजह से गाजा के हालात को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का रवैया थोड़ा तर्कहीन हो गया है। इस बीच, वॉशिंगटन हमास और इलाके के दूसरे हथियारबंद गुटों से हथियार हटाने की योजना को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी रखे हुए है। कुशनर ने ये बातें कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं, जहां वे रूस-यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों पर बातचीत के बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ मौजूद थे। गाजा के हालात पर बात करते हुए कुशनर ने कहा कि वॉशिंगटन और इस्राइल मोटे तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि वे क्या नतीजा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्राइल में 27 अक्टूबर को होने वाले नेसेट चुनाव से पहले घरेलू राजनीतिक वजहों से यह मामला उलझ रहा है। कुशनर ने कहा, 'हम इस्राइल में कुछ राजनीतिक मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अंतिम स्थिति को लेकर हम उनसे सहमत हैं। वहां अभी-अभी एक चुनाव हुआ है। इस वजह से कुछ मामलों में उनका व्यवहार थोड़ा अतार्किक हो गया है।' उनके ये बयान तब आए हैं जब इस्राइल ने 'बोर्ड ऑफ पीस' के उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें गाजा में हमास और दूसरे हथियारबंद गुटों के हथियार हटाने की बात कही गई है। यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें उस इलाके से इस्राइल सेना की वापसी भी शामिल होगी। अमेरिका इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस्राइल के विरोध की वजह से यह प्रक्रिया रुकी हुई है। दरअसल, कुशनर, जो गाजा को लेकर अमेरिकी कूटनीतिक कोशिशों में शामिल रहे हैं, उन्होंने वहां के हालात के बारे में निराशाजनक बात कही। उन्होंने कहा, 'गाजा में बहुत लंबे समय से हालात ठीक नहीं रहे हैं। इसे असल में एनजीओ और आतंकवादियों ने बनाया था। यह लंबे समय से एक बहुत बुरी जगह बन गया है।' ये बातें ऐसे समय में कही गईं जब गाजा पर इस्राइल के हमले जारी हैं। युद्ध के बाद की व्यवस्थाओं, खासकर हमास के हथियारों और इस्राइली सेना की वापसी के दायरे को लेकर मतभेद बने हुए हैं। शांति योजना में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के हथियार हटाने की प्रक्रिया को इस्राइली सेना की वापसी से जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इस प्रस्ताव को राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस्राइल ऐसी किसी भी व्यवस्था

होर्मुज बंद है या खुला: ट्रंप के दावे पर भी किया पलटवार

अमेरिकी जहाजों पर हमला करने के बाद क्या बोला ईरान?

तेहरान, एजेंसी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य की मौजूदा स्थिति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सीधे खारिज किया है। ईरानी सरकारी प्रसारक आईआरआईबी से बातचीत में रजाई ने कहा कि होर्मुज पूरी तरह बंद है और ट्रंप का यह कहना कि जलडमरूमध्य खुला है, 'बहुत बड़ा झूठ' है। उनके मुताबिक जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित रह गई है। रजाई ने यह भी कहा कि अमेरिका अगर ईरान को धमकी देना या उस पर हमला करना बंद कर देता है, तो ईरान होर्मुज को खुला रखने के लिए तैयार होगा। रजाई ने कहा कि होर्मुज बंद किए जाने से पहले इस रास्ते से 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। इन जहाजों के जरिये 10 करोड़ टन से ज्यादा सामान का परिवहन होता था।

अब उनके दावे के मुताबिक केवल सात से आठ जहाज ही इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं और इनमें ईरान की जरूरी वस्तुएं ले जाने वाले जहाज शामिल हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका से जुड़े कुछ जहाज चोरी-छिपे इस क्षेत्र से गुजरने की कोशिश करते हैं, जिन्हें ईरानी बल पहचानकर निशाना बनाते हैं। रजाई के अनुसार अमेरिका पांच से छह जहाजों को इस क्षेत्र से निकालने की कोशिश करता है और इन पर हमला किया जाता है।

ईरान होर्मुज के बाहर नया प्रतिबंधित क्षेत्र क्यों बना रहा है?: रजाई ने कहा कि आने वाले दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उनके मुताबिक यह क्षेत्र उस जगह से शुरू होगा, जिसे ईरान

अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की रेखा बता रहा है और यह फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि नए घोषित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ईरान की ओर से समुद्री आवाजाही पर लगाई जा रही पाबंदियां केवल होर्मुज जलडमरूमध्य तक सीमित नहीं रह सकती हैं।

ईरान ने अमेरिकी जहाजों को डुबोने से परहेज क्यों किया?: मोहसिन रजाई ने दावा किया कि ईरान अमेरिकी तस्करी वाले जहाजों को देख रहा है और उन्हें नष्ट भी कर रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि ईरान ने इन जहाजों को डुबाने का फैसला नहीं किया है। उनका तर्क है कि इन जहाजों में तेल होता है और उनके डूबने से क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। रजाई के मुताबिक ईरान ने कुछ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने के लिए चिह्नित किया था, लेकिन कुछ स्थानों पर जानबूझकर हमला नहीं किया गया। इनमें जॉर्डन का टाइटन बेस और इरबिल में मौजूद कुछ अमेरिकी ठिकाने शामिल हैं।

अमेरिका के साथ तनाव में होर्मुज इतना अहम क्यों है?: होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच यहां जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। रजाई ने कहा कि होर्मुज को खुला रखने का भविष्य सीधे तौर पर अमेरिका के सैन्य रवैये से जुड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका ईरान को धमकी देता रहेगा या उस पर हमला करेगा, तब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी। इस बीच नया प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने की चेतावनी से फारस की खाड़ी में समुद्री यातायात को लेकर चिंता और बढ़ सकती है।

लेबनान और हिजबुल्ला को लेकर ईरान ने क्या कहा?: मोहसिन रजाई ने लेबनान और हिजबुल्ला के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि युद्ध को केवल जीत और हार की लगातार श्रृंखला के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक युद्ध में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।

ईरान के नए कदम से आगे क्या बदल सकता है?: ईरान की ओर से होर्मुज के बाहर नया प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने की घोषणा तनाव को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। अभी रजाई के बयानों के अनुसार ईरान एक तरफ होर्मुज को अमेरिकी हमलों और धमकियों से जोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन समुद्री इलाकों में भी प्रतिबंध बढ़ाने की तैयारी कर रहा है जिन्हें वह अपने सुरक्षा हितों से जुड़ा मानता है।

चांद हमारा है': अमेरिकी झंडे के साथ शेयर की तस्वीर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया नया दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि चंद्रमा अमेरिका का है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर चंद्रमा की एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर 'चंद्रमा हमारा है' लिखा था। उन्होंने तस्वीर के साथ अमेरिकी झंडा भी लगाया। चंद्रमा की तस्वीर पोस्ट करने से कुछ मिनट पहले, ट्रंप ने अमेरिकी अंतरिक्ष बल की नई काली वर्दी की एआई-जनरेटेड तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने रंगों का वर्णन 'स्पेस ग्रे, मिडनाइट ब्लैक, सिल्वर ग्रे और सैटिन ब्लैक' के रूप में किया। वर्दी में कंधे और कॉलर पर प्रतीक चिन्ह, आस्तीन पर पैच और एक बेल्ट थी।

वहीं, ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में न्यू मैक्सिको का नाम बदलकर ' न्यू अमेरिका' रखने का भी सुझाव दिया। उन्होंने पोस्ट किया, 'कई लोगों ने न्यू मैक्सिको का नाम बदलकर। न्यू अमेरिका रखने का सुझाव दिया। उस संभावित रूप से अविश्वसनीय राज्य के लोगों के लिए यह कितना अधिक प्रतिष्ठित और सुंदर नाम होगा। वाह, मुझे यह बहुत पसंद आया।'व्हाइट हाउस ने इस विचार का समर्थन किया। एक पोस्ट में 'मेक्सिको' को काटकर उसकी जगह 'अमेरिका' लिखा हुआ दिखाया गया था।

न्यू मेक्सिको की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने फॉक्स न्यूज पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य का नाम विवाद का विषय नहीं है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्तित्व में आने से पहले से ही हमारा है।' उन्होंने कहा कि ट्रंप ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों से अमेरिकियों का ध्यान भटकाना चाहते हैं।

न्यू मेक्सिको को यह सुझाव देने से पहले एक आदेश जारी किया गया था। कुछ दिन पहले, ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार विवाद के बीच लेक ओंटारियो का नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने 27 अगस्त को ओवल ऑफिस से इस घोषणा की थी। लेक ओंटारियो कनाडा-अमेरिका सीमा पर स्थित पांच ग्रेट लेक्स में से एक है।

सुपरहीरो अंदाज में दिखे डोनाल्ड ट्रंप: सीमा पर दीवार लगाकर रोके अवैध अप्रवासी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राजनीति में अब सुपरहीरो का तड़का भी लग गया है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ग्रीन लैंटर्न थीम पर एक एआई वीडियो जारी किया है। वीडियो में ट्रंप को हरे रंग की रोशनी और सुपरहीरो जैसी ताकत के साथ दिखाया गया है, जो ग्रीन लैंटर्न के मशहूर पावर रिंग से प्रेरित है। व्हाइट हाउस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वीडियो साझा किया। इसके साथ ही लिखा, 'तेज धूप में हो या अंधेरी रात में, कोई बुराई मेरी नजर से नहीं बच पाएगी। जो लोग बुराई की ताकत की पूजा करते हैं, वे मेरी शक्ति से सावधान रहें। ग्रीन लैंटर्न की रोशनी!'

वीडियो में क्या नजर आ रहा है? : वीडियो में ट्रंप एक चमकती अंगूठी उठाते और एक चमकदार हरी सीमा दीवार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो प्रशासन की आव्रजन नीतियों का संकेत है। इसके बाद वे अपनी शक्तियों का उपयोग अमेरिकी विनिर्माण और सैन्य प्रयासों को बढ़ाने के लिए करते हैं।

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 31 अगस्त को एक वीडियो साझा किया था। इसमें वे खर्ग आईलैंड पर जोरदार धमाकों होते नजर आ रहे थे। वीडियो साझा करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि द्वीप को 'टुकड़े-टुकड़े' किया जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 'खर्ग आईलैंड के टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं।' हालांकि, उन्होंने इसके अलावा हमले को लेकर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। ट्रंप के पोस्ट में दिखाई गई तस्वीरों में खर्ग आईलैंड पर बड़े धमाके होते नजर आ रहे हैं। खार्ग द्वीप ईरान का एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र है, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल के हमलों के साथ युद्ध शुरू होने से पहले देश के लगभग 90% तेल निर्यात का संचालन करता था। द्वीप को कोई भी महत्वपूर्ण क्षति ईरान के तेल व्यापार को बाधित कर सकती है और उसकी अर्थव्यवस्था पर और दबाव डाल सकती है।

दुनिया के नक्शे पर भारत के वोट से क्यों तिलमिलाया पाकिस्तान?:

कश्मीर पर फिर अलापा पुराना राग

इस्लामाबाद, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के नक्शे को लेकर आए एक प्रस्ताव पर भारत के समर्थन के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बयानबाजी फिर तेज हो गई है। भारत ने 4 सितंबर को अपनाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस वोट का मकसद केवल दुनिया के नक्शों में महाद्वीपों के आकार को ज्यादा सही तरीके से दिखाने के सिद्धांत का समर्थन करना था। भारत ने यह भी साफ किया कि प्रस्ताव का जम्मू-कश्मीर, लद्दाख या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के राजनीतिक दर्जे से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के रुख को निशाना बनाया और जम्मू-कश्मीर पर अपने पुराने दावे दोहरा दिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर को दुनिया के नक्शे में महाद्वीपों के आकार को ज्यादा सही तरीके से दिखाने से जुड़ा प्रस्ताव अपनाया। इसका उद्देश्य ऐसे नक्शों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जिनमें अलग-अलग महाद्वीपों का क्षेत्रफल वास्तविक आकार के अनुपात में ज्यादा सही नजर आए। भारत ने इस

प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने वोट की व्याख्या में समान क्षेत्रफल वाले नक्शों के सिद्धांत को समर्थन देने की बात रखी। यानी भारत का वोट किसी राजनीतिक सीमा या विवादित क्षेत्र के समर्थन में नहीं था।

भारत ने जम्मू-कश्मीर पर क्या साफ किया? : भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव किसी खास विश्व नक्शे को मंजूरी नहीं देता। न ही यह किसी खास नक्शा बनाने की पद्धति या राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण को मान्यता देता है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नाम से जुड़े राजनीतिक नक्शों पर कोई फैसला नहीं किया गया है। भारत ने साथ ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर रुख को स्पष्ट, लगातार एक जैसा और गैर-परक्राम्य बताया। ऐसे में भारत के अनुसार इस प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर के दर्जे से जोड़ना सही नहीं है।

पाकिस्तान ने भारत के बयान पर क्या कहा? : भारत के स्पष्टीकरण के एक दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने भारत के दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत के रुख को बेबुनियाद बताया। उसने कहा कि भारत की कथित एकतरफा कार्रवाई और जम्मू-कश्मीर पर उसका नियंत्रण क्षेत्र की स्थिति को नहीं बदल सकता। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में लंबे समय से लंबित विवाद बताया और इस मुद्दे पर अपने पुराने रुख को दोहराया।

अमेरिका को समझ आ रहा: बच्चों की परवरिश माता-पिता ही बेहतर करेंगे, डे-केयर से दूरी बनाने के लिए बनी खास योजना

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसमें छोटे बच्चों को पालने के लिए नौकरी छोड़कर घर पर रहने वाले माता-पिता में से किसी एक अभिभावक को वित्तीय मदद दी जाएगी। दरअसल, अमेरिका अब पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों की ओर लौट रहा है जिसमें माना जाता है कि छोटे बच्चों की देखभाल डे-केयर के बजाय माता-पिता की निगरानी में होनी चाहिए।

ट्रंप प्रशासन ने इस संबंध में बाकायदा योजना का मसौदा भी तैयार कर लिया है। यह योजना मुख्यतः उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पहल का नतीजा है, जो लंबे समय से इसकी वकालत करते रहे हैं कि छोटे बच्चों को डे-केयर के मुकाबले घरेलू माहौल मिलना चाहिए, जो उनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। मसौदे के मुताबिक, प्रस्तावित योजना का लाभ केवल उन विवाहित जोड़ों पर लागू होगा जिनमें एक जीवनसाथी काम करता है और दूसरा घर पर बच्चों

की देखभाल करता है। अविवाहित जोड़े या एकल अभिभावक इसके दायरे से बाहर रहेंगे। योजना को लागू करने के लिए चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट फंड (सीसीडीएफ) के पैसे का उपयोग किया जाएगा। रूढ़िवादी विचारकों और हेरिटेज फाउंडेशन जैसे संगठनों ने इस कदम का समर्थन किया है। उनका मानना है कि यह नियम व्यावसायिक डे-केयर और घर पर बच्चों की परवरिश करने वाले माता-पिता के बीच भेदभाव को खत्म करेगा। व्हाइट हाउस और उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन नियम को अंतिम रूप दिए जाने से पहले इसे जनता की प्रतिक्रिया के लिए ऑनलाइन जारी किया जाएगा।चाइल्ड केयर सब्सिडी फंड से उन कामकाजी माता-पिता या पढ़ाई/ट्रेनिंग कर रहे अभिभावकों को सब्सिडी मिलती है, जिनकी पारिवारिक आय उनके राज्य की औसत आय के 85% से कम हो।

यह मदद 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मिलती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सीसीएस फंड से मदद पाने वाले परिवारों में करीब 80% परिवार एकल कामकाजी माता-पिता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या अकेली मांओं की है।ट्रंप प्रशासन को इस बदलाव के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी और इसे अगले वर्ष तक लागू किया सकता है।

यमन में फिर भड़की जंग: हूतियों और सेना में भीषण लड़ाई, चार दिन में 117 लोगों की हुई मौत

एडेन, एजेंसी। पश्चिमी प्रांतों ताइज और होदेइदाह में यमनी सरकारी सेना और हूती समूह के बीच चार दिनों से भीषण झड़प चल रही है। इसमें अबतक कम से कम 117 लोग मारे गए हैं। यह जानकारी मेडिकल अधिकारियों ने दी। पश्चिमी तट के मोर्चे पर सरकारी सेना के साथ मौजूद एक वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर शिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि गुरुवार को लड़ाई शुरू होने के बाद से सरकारी सेना के 54 सैनिक मारे गए हैं। कई अन्य घायल हुए हैं।

वहीं, पश्चिमी होदेइदाह प्रांत में हूती -नियंत्रित अस्पतालों के दो मेडिकल सूत्रों ने बताया कि इसी दौरान हूती समूह के 63 सदस्य मारे गए, जिससे दोनों पक्षों की कुल मरने वालों की संख्या 117 हो गई।

यमनी सरकार के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को होदेइदाह और ताइज के पश्चिमी प्रांतों में हूती -नियंत्रित इलाकों पर हमले किए। ये हमले रणनीतिक बाब अल-मंदाब जलडमरूमध्य के पास हूती समूह के बड़े हमले का सामना कर रही जमीनी सेना की मदद के लिए किए गए थे।अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये हवाई हमले ऐसे समय में किए गए जब दोनों प्रांतों में कई मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। हूती लड़ाकों ने पिछले 24 घंटों में तेजी से आगे बढ़ते हुए कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था।अधिकारी ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने उन इलाकों में हूती ठिकानों और गतिविधियों को निशाना बनाया जहां जमीनी लड़ाई चल रही थी। हमलों या हताहतों के बारे में और जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकी।

सरकार के एक सैन्य अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर शिन्हुआ को बताया कि हूती सदस्यों द्वारा कब्जा किए जाने के कुछ ही घंटों बाद, सरकारी सेना ने रात भर चले एक तेज जवाबी हमले में पश्चिमी ताइज में कई महत्वपूर्ण ठिकानों को वापस अपने कब्जे में ले लिया।हालिया तनाव पश्चिमी यमन में पिछले कुछ वर्षों की सबसे भीषण जमीनी लड़ाइयों में से एक है। इससे देश के कई मोर्चों पर वर्षों की सापेक्ष शांति के बाद बड़े पैमाने पर लड़ाई फिर से शुरू होने की चिंता बढ़ गई है।यमन 2014 के अंत से ही संघर्ष में फंसा हुआ है, जब हूती समूह ने सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के समर्थन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अगले साल हस्तक्षेप किया था।

नेपाल जलप्रलय के 12 दिन: पानी हुआ जहरीला, संपर्क में आते ही त्वचा पर इंफेक्शन; आंसुओं के बीच नुकसान के आंकड़े

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल आपदा के बाद भारत में आया सैलाब अब दिन-ब-दिन जहरीला होता जा रहा है। इसके संपर्क में आते ही लोगों के पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल जाता है। लोग खुजली से परेशान हैं। यह परेशानी तब और बढ़ रही है जब संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंच रहा है। ऐसे में इसकी चेन को ब्रेक करना बेहद मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले इसकी चपेट में वे बुजुर्ग आए जो आपदा के बाद खेतों में काम करने गए। अब उनसे यह संक्रमण घर के दूसरे लोगों में पहुंच रहा है। शरीर में अलग-अलग जगहों पर निशान पड़ रहे है। इसकी जद में कुशीनगर और महाराजगंज के कई गांव हैं।

महाराजगंज जिला अस्पताल के वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. एके द्विवेदी

ने कहा कि पानी में ई. कोलाई और अन्य फीकल बैक्टीरिया पनपने की अधिक संभावना है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पानी के संपर्क में आता है तो बैक्टीरिया सबसे पहले त्वचा की ऊपरी परत को कमजोर कर देता है। कुशीनगर जिले के पीपरीघाट निवासी रामायण सिंह ने बताया कि खेत में काम करने के दौरान उनके पैर नेपाल से आए दूषित पानी के संपर्क में आ गए थे। इसके तुरंत बाद खुजली शुरू हो गई। सेवरही की रंभा देवी की बेटी के शरीर पर दाने हो गए हैं। आपदा के 12वें दिन चीन ने पहली बार कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों को गिरयोंग काउंटी जाने की अनुमति दी। अब चीन के सीमावर्ती इलाके में तबाही की असली तस्वीर सामने आई। यह आव्रजन चौकी बुरी तरह तबाह हो चुकी है। यहां तक कि यह पता लगाना भी मुश्किल है कि इसका ढांचा कहां पर खड़ा था।

नेपाल में अचानक बाढ़ से मची तबाही के 12 दिन बीतने बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति विकट बनी हुई है। राहत एवं बचाव कार्य बदस्तूर जारी है। मलबे को हटाने, सड़कों को दुरुस्त करने और संचार व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं। नेपाली सेना और इंजीनियरों की टीम अस्थायी पुल बनाने और प्रभावित लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने में जुटी है। अपेक्षाकृत कम प्रभावित क्षेत्रों में कुछ लोग घरों की ओर लौटे हैं और अपनों को खोने के दर्द के बीच जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। अपने टूटे-फूटे घरों को फिर से ठीक करके रहने लायक बना रहे हैं। एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा है। लोग इसमें अपना बचा-खुचा सामान तलाश रहे हैं। उनका कहना है कि समझ ही नहीं आ रहा कि जिंदगी फिर कहां से शुरू करें।

खुद बचे, अब राहत अभियान में जुटे

सुदीप कुमार न्यौपाने (31) विनाशकारी बाढ़ में बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनके छोटे भाई और एक करीबी सहयोगी लापता हैं। न्यौपाने अब राहत कार्यों में शामिल हो गए और रसुवा में विस्थापित लोगों के बीच भोजन तथा अन्य जरूरी सहायता सामग्री के वितरण में मदद कर रहे हैं।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशक: सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश आत्महत्या केस में बड़ा खुलासा

पहले प्यार के जाल में फंसाया,फिर ब्लैकमेलिंग

महिला, पिता और वकील गिरफ्तार

बस्ती में हनीट्रैप का बड़ा खुलासा

क्रांति समय www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com www.epaper.krantisamay.com

बस्ती: हनीट्रैप का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के बस्ती से सामने आया है। यहां वाल्टरगंज थाने के दरोगा सूर्य प्रकाश सिंह ने बीते दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब जांच के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक, वाल्टरगंज के थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह हनीट्रैप का शिकार हो गए थे। प्रियंका चौधरी नाम की एक महिला उन्हें वीडियो कॉल और चैट के जरिए ब्लैकमेल करती थी। पहले उसने थानाध्यक्ष से करीबी संबंध बनाए और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सूर्य प्रकाश सिंह उसकी मांगें पूरी करते रहे। लेकिन जब प्रियंका की मांगें लगातार बढ़ती गईं, तो उन्होंने कथित तौर पर मौत को गले लगा लिया।

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रियंका की हनीट्रैप की साजिश में उसके पिता रामनयन चौधरी भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार, दोनों पिता-पुत्री मिलकर पहले भी कई लोगों को हनीट्रैप का शिकार बना चुके थे और उनसे लाखों रुपये ऐंठ चुके थे।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में थाना वाल्टरगंज के पूर्व थानाध्यक्ष स्वर्गीय सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा किए गए आत्मघाती कदम के पीछे की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए बस्ती पुलिस ने एक बड़े और शातिर हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट को संचालित करने वाली मुख्य आरोपी महिला, उसके पिता और गिरोह के कानूनी सलाहकार बने वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एक अभियान के तहत कोतवाली पुलिस व सर्विलांस टीम ने रविवार सुबह 07:55 बजे सदर अस्पताल चौराहे के पास से तीनों आरोपियों को दबोच लिया. इनके पास से अपराध में इस्तेमाल की जाने वाली एक बोलेरो गाड़ी (UP51BN5805) और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

पुलिस पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं. मुख्य आरोपी प्रियंका चौधरी (उम्र 32 वर्ष) पिछले 10 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी और मुंबई में ब्यूटी पार्लर व स्पा सेंटरों में काम करती थी. वह संपन्न और रसूखदार व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाती थी. ब्लैकमेल करने के लिए महिला वीडियो कॉल पर ही अपने हाथ की नस काटकर खून बहाने का नाटक करती थी, जिससे शिकार भावनात्मक रूप से बुरी तरह डर जाता था. इस घिनौने खेल में प्रियंका का पिता रामनयन चौधरी और वकील विजय प्रकाश यादव बराबर के हिस्सेदार थे. कानूनी दांव-पेच से डराने और वसूली की पूरी योजना वकील विजय प्रकाश तैयार करता था.

जांच में अब तक गिरोह द्वारा लाखों रुपये की धनउगाही का ब्यौरा मिला है,

जिसमें अपने ही मकान मालिक डॉक्टर उमेश को जाल में फंसाकर 4 लाख ऐंठे ड्राइवर अहमद रज़ा से 5 लाख की उगाही की. मध्य प्रदेश के रहने वाले व्यापारी आर्यन दीक्षित को जाल में फंसाकर 15 लाख की बड़ी रकम वसूली. आखिरी शिकार वाल्टरगंज के थाना प्रभारी बने, एसओ सूर्य प्रकाश सिंह को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के गहन विश्लेषण से यह पुख्ता हुआ है कि थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह लगातार इस गिरोह के निशाने पर थे.

घटना वाले दिन यानी 29 अगस्त 2026 को आरोपी वकील विजय प्रकाश ने ही दोपहर 1:41 बजे थानाध्यक्ष को अंतिम कॉल की थी.

लगातार दी जा रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार थानाध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपने सरकारी आवास में फंदा लगा लिया. हनीट्रैप से प्रताड़ित होकर सूर्य प्रकाश ने जान दी पुलिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और कॉलिंग पैटर्न के विश्लेषण में सूर्य प्रकाश सिंह का संपर्क प्रियंका और विजय प्रकाश से होने की पुष्टि हुई है. पुलिस का दावा है कि घटना वाले दिन विजय प्रकाश ने दोपहर 1:41 बजे सूर्य प्रकाश सिंह को आखिरी कॉल की थी.

> इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के गहन विश्लेषण से यह पुख्ता हुआ है कि थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह लगातार इस गिरोह के निशाने पर थे. घटना वाले दिन यानी 29 अगस्त 2026 को आरोपी वकील विजय प्रकाश ने ही दोपहर 1:41 बजे थानाध्यक्ष को अंतिम कॉल की थी. लगातार दी जा रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार थानाध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपने सरकारी आवास में फंदा लगा लिया.

पुलिस का कहना है कि हनी ट्रैप और कथित प्रताड़ना से परेशान होकर ही सूर्य प्रकाश सिंह ने आत्महत्या की. मामले में मृतक के पुत्र संदीप सिंह की ओर से 5 सितंबर को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली बस्ती में म0अ0सं0 387/2026, धारा 108 व 3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया.

पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती मंडल संजीव त्यागी का कहना है कि यह तो महज बानगी भर है. इस गिरोह के शिकार बने दर्जनों अन्य लोगों के संबंध में भी जांच तेजी से चल रही है. पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरों का खुलासा हो सकता है.

दरोगा सूर्यप्रकाश के मामले में जो तथ्य सामने आए उस के अनुसार पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया है. अभी तक ब्लैक मेलिंग के आरोपों की पुष्टि हुई है

जिससे परेशान होकर सूर्यप्रकाश ने आत्महत्या किया.फिलहाल सभी आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है.